www.tamsasanket.com
वर्षः 29 || अंक 195 || अम्बेडकरनगर
बुधवार
07 अक्टूबर 2026 || पृष्ठः 08 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव

दैनिक तमसा संकेत

https://epaper.tamsasanket.com
अम्बेडकर नगर व लखनऊ से एक साथ प्रकाशित

» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:01
सूर्यास्तः 05:47
अधिकतमः 31°00
न्यूनतमः 22°00



पेज 07

विशेष समाचार

बेहतर विकल्प एवं जरूरी ... >>पेज 04
कॉमेडियन को पकड़ने ... >>पेज 06
अरबाज की बेटी सिपारा का ...



8 घंटे के धरने के बाद राहुल-प्रियंका हिरासत में, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मार्च निकाला था

सीईसी के खिलाफ 5 दिन में 7वां प्रदर्शन

‘हमारे देश के साथ जो किया गया वो देशद्रोह’

आकाशवाणी के अंदर से बोले राहुल गांधी

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के दूसरे नेताओं ने अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए कोई प्रस्ताव या अपॉइंटमेंट नहीं मांगा है। वे बिना किसी अपॉइंटमेंट और एजेंडा के सीधे सीईसी के ऑफिस जाना चाहते हैं।

राहुल गांधी ने कहा, "आकाशवाणी भवन परिसर में प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर दिल्ली पुलिस को यहां प्रदर्शन से असुविधा है तो पुलिस उन्हें दूसरी जगह उपलब्ध करा सकती है। संविधान हमें प्रदर्शन करने का अधिकार देता है।" पुलिस अफसर ने प्रियंका गांधी से बात की और धरना खत्म की अपील की। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने हटने से मना कर दिया।

मांग

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ आकाशवाणी में धरने पर बैठे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हटाया है. इन दोनों नेताओं के अलावा केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा समेत कई और लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. इन्हें किंग्सवे कैंप ले जाने की जानकारी मिली है. फिलहाल आकाशवाणी परिसर को खाली कराया जा रहा है. इससे पहले बीते 8 घंटों से धरना दे रहे राहुल गांधी ने कांग्रेसियों के साथ मिलकर यहीं पर रात गुजारने की तैयारी कर ली थी. आकाशवाणी चुनाव आयोग की इमारत के एकदम पास में है. राहुल गांधी का कहना था कि हमें मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों से मिलना है. उनसे मिले बिना हम वापस नहीं लौटेंगे. इसका संदेश भी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजा था. कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के ख़िलाफ़ कांग्रेस का प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा. खरगे ने सभी सांसदों को दिल्ली में रहने के निर्देश दिए हैं।

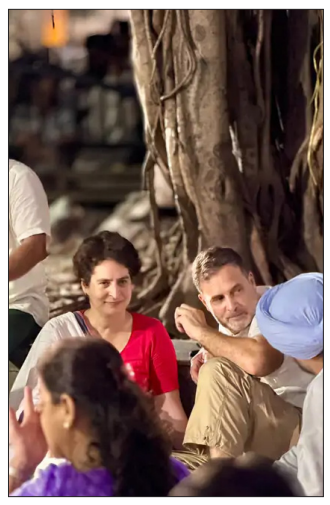
>> (शेष पेज 06 पर)



- विरोध प्रदर्शन के दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा, "दिल्ली पुलिस लोकतंत्र के हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालात ऐसे हैं। जो लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं, उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है।"

दिल्ली पुलिस बोली- राहुल के धरने से शहर का ट्रैफिक का बाधित हो रहा

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस फ़िलहाल कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आकाशवाणी भवन से नहीं हटाएगी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, रात के समय प्रदर्शनकारियों को हटाने की अभी कोई योजना नहीं है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं। पुलिस अलर्ट पर है क्योंकि विरोध प्रदर्शन के रात भर चलने की संभावना है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, राहुल से बातचीत चल रही है और उनसे स्वेच्छा से जाने का आग्रह किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन से पूरी नई दिल्ली में ट्रैफिक बाधित हो रहा है।



चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा- राहुल ने अबतक अपॉइंटमेंट नहीं मांगा

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी और INDI गठबंधन के दूसरे नेताओं ने अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए कोई प्रस्ताव या अपॉइंटमेंट नहीं मांगा है। वे बिना किसी अपॉइंटमेंट और एजेंडा के सीधे CEC के ऑफिस जाना चाहते हैं।

इंडिया ब्लॉक के मार्च की टाइम लाइन

- सुबह 10 बजे: विपक्षी सांसद संसद के मकर द्वार के पास इकट्ठा हुए।
- सुबह 10:30 बजे: सांसदों का मार्च शुरू हुआ।
- सुबह 11 बजे: दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को आकाशवाणी के ऑफिस के सामने रोका। सांसद धरने पर बैठे।
- सुबह 11:40 बजे: राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए।
- दोपहर 12:05 बजे: पुलिस ने राहुल समेत विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया।
- दोपहर 12:10 बजे: राहुल आकाशवाणी के ऑफिस में घुसे।
- दोपहर 12:25 बजे: राहुल-प्रियंका आकाशवाणी ऑफिस में धरने पर बैठे।
- शाम 6 बजे: राहुल गांधी ने कहा- "हम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर ही रहेंगे।"

बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीटों पर वोटिंग खत्म

सबसे ज्यादा 83.86% वोटिंग मदुरंतकम में दर्ज

मतदान

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। देश के चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 सीटों पर मंगलवार हुई वोटिंग शाम 6.00 बजे खत्म हो गई। शाम 5 बजे तक के वोटर टर्नआउट में सबसे ज्यादा 83.86% वोटिंग तमिलनाडु के मदुरंतकम में दर्ज की गई।

वहीं, आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके पार्टी कार्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन पर चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनके बेटे गुलाम नबी आजाद भी रेजीनगर से उम्मीदवार हैं।

मीडिया से बात करते हुए नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को जबरन उठा दिया गया था।

>> (शेष पेज 06 पर)



- नंदीग्राम और रेजीनगर में वोटिंग खत्म
- तमिलनाडु के धारापुरम में मतदान अधिकारी को हटाया गया

असम के जागीरोड में देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट

ट्रायल रन शुरू रोज बनेगी 4.8 करोड़ चिप

तकनीक

तमसा संकेत, एजेंसी

जागीरोड। असम के जागीरोड, मोरीगांव में बन रहा टाटा समूह का सेमीकंडक्टर प्लांट देश का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है। पूरी तरह से चालू होने पर इस प्लांट की उत्पादन क्षमता रोजाना करीब 4.8 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप तक होने की उम्मीद है। करीब 592 एकड़ में फैले इस प्लांट में ट्रायल रन शुरू हो चुका है। यहां वायर बॉन्डिंग, फ्लिप चिप और फैन-आउट जैसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। वहीं चिप से ऑटोमोटिव, हेल्थकेयर, टेलीकम्युनिकेशन और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों की जरूरत पूरी होगी। प्लांट बना रही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मुताबिक, यह प्लांट 27 से 40 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने की क्षमता रखता है।

>> (शेष पेज 06 पर)



- विदेश की नौकरी छोड़कर असम के युवा दे रहे इंटरव्यू

राहुल बोले- संविधान हमें प्रदर्शन करने का अधिकार देता है

राहुल गांधी ने कहा, आकाशवाणी भवन परिसर में प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर दिल्ली पुलिस को यहा प्रदर्शन से असुविधा है तो पुलिस उन्हें दूसरी जगह उपलब्ध करा सकती है। संविधान हमें प्रदर्शन करने का अधिकार देता है।

फास्ट न्यूज

सड़क पर खड़े ट्रेलर में घुसी कार 7 की मौत

भावनगर । गुजरात के भावनगर-सोमनाथ नेशनल हाईवे पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा शिव शक्ति होटल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बोलेरो एसयूवी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के पीछे जा टकराई।

विवाद सुनवाई

शिवसेना चुनाव चिह्न विवाद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को शिवसेना के चुनाव चिह्न विवाद पर सुनवाई हुई। इस दौरान CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पूछा कि क्या उन लोगों को पार्टी का निशान दिया जा सकता है जिन्होंने दलबदल जैसा संवैधानिक पाप किया है? कोर्ट यह जानना चाहता है कि क्या सिर्फ विधायकों की संख्या को ही एकमात्र पैमाना मानना सही है, जबकि उन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई कोर्ट में चल रही हो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पूछा था कि चुनाव आयोग दोनों गुटों को धनुष-बाण निशान देने से इनकार क्यों नहीं किया था।

तेलंगाना में अवैध फॉर्म 7 के मामले में पहली एफआईआर

हैदराबाद । हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली में पुलिस ने भाजपा के एक बूथ लेवल एजेंट खिलाफ मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में 30 मुस्लिम व्यक्तियों के नाम पर फर्जी फॉर्म 7 भरने के आरोप में FIR दर्ज की है। SIR के तहत दावे-आपत्तियां खत्म होने से एक दिन पहले पुलिस ने यह कार्रवाई की।

सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों ने ली शपथ

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पद की शपथ दिलाई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को 3 नए जज मिले। CJI जस्टिस सूर्यकांत ने गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट के जज पद की शपथ दिलाई।

तीनों की नियुक्ति के साथ ही शीर्ष अदालत में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को तीनों नामों की सिफारिश की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।



- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 सितंबर को तीनों जजों के प्रमोशन की सिफारिश की थी।

जस्टिस सुनीता का जन्म 30 अप्रैल 1966 को फैजाबाद , उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइंस की पढ़ाई की और अवध यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली।

>> (शेष पेज 06 पर)

सीएम योगी बोले पहले बिजली कुछ परिवारों के लिए पेटेंट थी, अब हर घर मिल रही

‘पिछले 9.5 साल में यूपी बदला’

शुभारंभ

हेमन्त कृष्ण

तमसा संकेत, लखनऊ । सीएम योगी ने लखनऊ में कहा है कि पिछले 9.5 सालों में यूपी बदल चुका है। पहले बिजली कुछ परिवारों के लिए पेटेंट थी। अब हर घर में मिल रही है। 10 साल पहले प्रदेश का युवा अन्य जगहों पर रोजगार के लिए भटकता था। आज युवाओं को लखनऊ के अंदर ही कैरियर बनाने का अवसर मिल रहा है। यहां तक कि दुनिया भर के युवाओं को करियर के लिए लखनऊ आना पड़ रहा है।

सीएम योगी ये बातें मंगलवार को HCL Tech के 10 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस पर कहीं। उन्होंने HCL GUVI एमर्जिंग टेक स्किलिंग सेंटर का शुभारंभ किया। केंद्र के जरिए युवाओं को नई तकनीक से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 एकड़ में बनने जा रहे HCL IT सिटी फेज 2 के निर्माण की भी शुरुआत की। इस दौरान HCL समूह की चेयरमैन रोशनी नादर भी मौजूद रहीं। HCL की पांच दशक की यात्रा पर कंपनी को बधाई।

>> (शेष पेज 06 पर)





> दस साल पहले इस कैंपस की यात्रा करीब 100 युवाओं से शुरू हुई थी और आज यहां साढ़े 12 हजार युवा काम कर रहे हैं। यह बदलाव दिखाता है कि अवसर मिलने पर यूपी का युवा कहीं पीछे नहीं है। योगी

लखनऊ को 10 साल में डीप टेक का केंद्र बनाना होगा

सीएम योगी ने कहा- HCL के लखनऊ कैंपस के अगले चरण में सिर्फ IT सर्विसेज तक सीमित नहीं रहना है। अगले दस साल में लखनऊ को AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी और डीप टेक का केंद्र बनाना होगा। इसके लिए अभी से तैयारी करनी होगी। उन्होंने कहा कि यूपी की सबसे बड़ी ताकत यहां की युवा आबादी, युवा वर्कफोर्स और प्रतिभा है।

बेटियां नाइट शिफ्ट करके सुरक्षित घर लौट रही हैं

सीएम ने कहा- करीब नौ साल पहले जब उन्होंने पूछा था कि कितनी बेटियां और बहनें नाइट शिफ्ट में काम करती हैं, तो जवाब मिला था कि यूपी में नाइट शिफ्ट की कल्पना नहीं की जाती। आज बेटियां और महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं और सुरक्षित अपने घर लौट रही हैं। करीब दस साल पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर अलग स्थिति थी। पुलिस को देखकर अपराधी और माफिया डरते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। आज पुलिस की गाड़ी देखकर अपराधियों में डर पैदा होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा और रोजगार के बेहतर माहौल से युवाओं को अपने ही राज्य में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।

पदग्रहण : कार्यकाल 2028 तक, 20 तरह के लड़ाकू जहाज उड़ाने में माहिर, कारगिल जंग में भी शामिल रहे

वायुसेना के नए प्रमुख बने आशुतोष दीक्षित

तमसा संकेत, एजेंसी

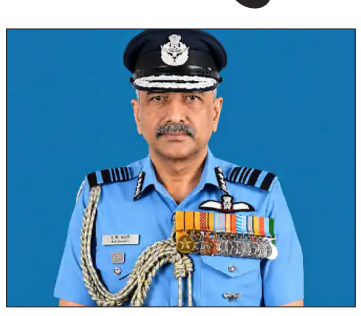
नई दिल्ली । एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के नए प्रमुख होंगे। वह 31 अक्टूबर को 29वें एयर चीफ मार्शल का कार्यभार ग्रहण करेंगे। वे अभी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। उन्होंने 1 जुलाई 2026 को यह पदभार संभाला था।

आशुतोष दीक्षित कारगिल जंग में भी शामिल थे। उन्होंने फाइटर जेट से घुसपैठियों पर बम गिराए थे। वह 20 तरह की लड़ाकू विमान उड़ाने में माहिर हैं।

एयर मार्शल दीक्षित को 6 दिसंबर 1986 को IAF की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।

आशुतोष दीक्षित वायुसेना में टेस्ट पायलट हैं। टेस्ट पायलट सबसे कुशल पायलट माने जाते हैं। इसका काम विमान को उसकी अंतिम सीमाओं तक ले जाकर टेस्ट करना होता है। सेना की खेप में जब भी कोई नया विमान आता है उसे पहली बार टेस्ट पायलट ही आसमान में लेकर जाते हैं। उड़ान के दौरान विमान के कंट्रोल, स्थिरता और तकनीकी ग्लिच की जांच करते हैं।

>> (शेष पेज 06 पर)



- आशुतोष दीक्षित 31 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगे।

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे

आशुतोष दीक्षित एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख बने थे। वह 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। वह ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और फ्रंटलाइन एयर बेस की कमान भी संभाल चुके हैं।



- आशुतोष दीक्षित एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे, जो 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख बने थे। वह 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। वह ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और फ्रंटलाइन एयर बेस की कमान भी संभाल चुके हैं।

एयर मार्शल दीक्षित ने 3500 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी

एयर मार्शल दीक्षित 29वें वायुसेना प्रमुख होंगे। उन्हें करीब 40 साल का सर्विस अनुभव है। उन्होंने मिराज-2000, मिग के अलग-अलग वर्जन, जगुआर, तेजस, हॉक, IL-78, AN-32, किरण, HPT-32 और एवरो जैसे कई विमानों को उड़ाया है। वे एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हैं। उन्होंने अब तक 3500 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी है।

उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप-इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों और सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लिया है।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव

राष्ट्र प्रथम, नागरिक प्रथम सिद्धांत पर आधारित असाधारण यात्रा

बधाई

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष तक निरंतर नेतृत्व पूर्ण करने पर बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि यह मात्र एक औपचारिक सम्मान से कहीं अधिक राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम के सिद्धांत से निर्देशित प्रधानमंत्री मोदी की असाधारण यात्रा का उत्सव है।

साथ ही यह गुजरात में तीन बार मिले प्रचंड जनादेश और लगातार तीन लोकसभा चुनावों में मिले समर्थन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता का अटूट विश्वास झलकता है। प्रस्ताव में उनकी 10 प्रमुख विशेषताओं को गिनाया गया, जो गुजरात और उसके बाद भारत में उनके नेतृत्व को जोड़ने वाले अखंड सूत्र को दिखाता है।

प्रस्ताव में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 2025 का ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति की नई सीमाएं तय करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की गई। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाने, एक रैंक एक पेंशन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के सृजन को भी उल्लेख किया गया।

>> (शेष पेज 06 पर)



अखिलेश हिरासत में, यूपी में सड़कों पर उतरे सपाई आगरा में झड़प, पुलिसवाले ने थप्पड़ मारे, लखनऊ में सड़क पर घसीटा

अखिलेश हिरासत में, यूपी में सड़कों पर उतरे सपाई

विरोध

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ/गोरखपुर। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में 19 विपक्षी पार्टियों के सेव डेमोक्रेसी मार्च को पुलिस ने रोक दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। इसके विरोध में मंगलवार को प्रदेशभर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। गोरखपुर में सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और वोट चोर इस्तीफा दो के नारे लगाए।

वहीं, लखनऊ में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को सड़क पर घसीटा। आगरा में सपाइयों से



धक्का-मुक्की के बीच पुलिसवाले CEC का पुतला छीनकर भाग गए। एक पुलिसकर्मी ने टांग अड़ाकर एक सपा कार्यकर्ता को जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसे थप्पड़ मारा और फिर लात मारी। आगरा में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच उस समय नोकझोंक हो गई, जब कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने का प्रयास किया। पुलिस ने पुतला फूंकने से रोकने की कोशिश की, तो दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान धक्का-मुक्की हुई। एक



बहराइच में पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं में धक्का-मुक्की

बहराइच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की खबर के बाद मंगलवार दोपहर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। दोपहर 3 बजे जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव की अगुवाई में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हो गए।

उन्होंने अखिलेश यादव की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर रास्ता रोक दिया, जिससे जाम लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, तो दोनों पक्षों में झड़प हुई। देखते ही देखते पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष रामहर्ष यादव की पुलिस से झड़प हो गई। इसके अलावा महिला कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की होने की बात भी सामने आई है।

> लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सपा कायकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी भी की। पुलिस ने भी कई कार्यकर्ताओं को उठाकर बस में बैठाकर ले गई।

पुलिसकर्मी ने टांग अड़ाकर एक सपा कार्यकर्ता को जमीन पर गिरा दिया। पुलिसवाले सपा कार्यकर्ताओं से मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला छीनकर भा गए। मऊ में दोपहर करीब 2 बजे प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेने का



बरेली में सपाइयों ने सीईसी का पुतला फूंका

बरेली में चौकी चौराहे पर सपाइयों ने भाजपा का झंडा और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के झंडे को जूतों से भी कुचला। पुलिसकर्मियों ने झंडे और पुतले को आग से बचाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान हुई, लेकिन पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं सकी। इसके बाद सपाइयों ने झंडे और पुतले में आग लगा दी।

प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और सपा नेताओं के बीच

> वहीं, दिल्ली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा-अगर ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष हैं, तो उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। यह लोकतंत्र बचाने की बात है। पुलिस को बच्चों के साथ और प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए।

लखनऊ में सपाइयों की पुलिस से धक्का-मुक्की

लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा।

धक्का-मुक्की हो गई। लखनऊ में सपा कार्यकर्ता ने कहा- अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेता ऐसे रोड पर धरना प्रदर्शन करके गिरफ्तारी देंगे। चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा।

फास्ट न्यूज

बीएचयू में 10 जगहों पर हुआ कुलपति का पुतला दहन

वाराणसी । काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के चीफ प्रॉक्टर हटाओ' आंदोलन के 14 वें दिन बीएचयू परिसर में 10 अलग-अलग स्थानों पर कुलपति का पुलता दहन किया गया। संगठन का कहना है कि करीब दो महीने पहले मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया था। हमने प्रशासन से अपने मांगों को लेकर हर संभव संवाद करने की कोशिश की पर कोई समाधान नहीं निकल रहा है।

बाराबंकी कचहरी में वाहनों की एंट्री बंद

बाराबंकी । बाराबंकी में जिला न्यायालय परिसर के गेट नंबर-1 से अधिवक्ताओं के वाहनों की एंट्री बंद करने का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार सुबह 10:30 बजे को जिला बार एसोसिएशन के बुलावे पर अध्यक्ष रमन लाल द्विवेदी, महामंत्री प्रदीप श्रीवास्तव, मंत्री प्रकाशन अमित सिंह सूर्यवंशी, पुस्तकालय अध्यक्ष रूबी सिंह समेत सैकड़ों अधिवक्ता सामूहिक अवकाश पर रहे। उन्होंने गेट नंबर-1 के सामने धरना प्रदर्शन कर जिला जज के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने कहा कि रोक से बुजुर्ग और चलने में असमर्थ अधिवक्ताओं को परेशानी हो रही है।

फतेहपुर पुलिस ने फर्जीवाड़े के दो आरोपी पकड़े

फतेहपुर। फतेहपुर कोतवाली पुलिस ने फर्जीवाड़े के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक महिला की संपत्ति और शादी से जुड़े दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में सीतापुर के राजाराम वर्मा उर्फ पप्पू वर्मा और बाराबंकी के राजकुमार उर्फ पिंकू वर्मा शामिल हैं। पुलिस को इनकी फतेहपुर कोतवाली में दर्ज एक मामले में तलाश थी।

अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सपा का जोरदार प्रदर्शन



तमसा संकेत, संवाददाता

अम्बेडकरनगर। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को अम्बेडकरनगर में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के पास सपा कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं अकबरपुर विधायक राम अचल राजभर ने किया। धरने को संबोधित करते हुए राम अचल राजभर ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, जनहित और लोकतांत्रिक अधिकारों की आवाज उठाने के कारण अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। सपा नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव की रिहाई तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'वोट बचाओ, देश बचाओ और संविधान बचाओ' के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाए। धरने के दौरान सपा की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। राम अचल राजभर ने आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग दोहराते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर जनता के विश्वास को बनाए रखना जरूरी है।

बोले- समान काम की मिले बराबर सैलरी, 7 अक्टूबर तक चलेगा धरना

गोरखपुर में एनएचएम कर्मचारियों का सीएमओ ऑफिस पर प्रदर्शन

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर । गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतन और नौकरी की गारंटी देने की मांग उठाई।

प्रदर्शन में जिले और राज्य स्तर के डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि समान काम करने के बावजूद वेतन और सुविधाओं में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने न्यूनतम 18



> कर्मचारियों ने साफ किया कि उनका धरना-प्रदर्शन 7 अक्टूबर तक लगातार चलेगा। इस दौरान वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध दर्ज कराते रहेंगे।

हजार रुपए वेतन तय करने की मांग भी रखी। प्रदर्शन में शामिल CHC चरगांवा की डॉक्टर स्वाति ने कहा- 2008 में मेरी पोस्टिंग यहां इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डॉक्टर के तौर पर हुई थी। इतने वर्षों से निष्ठापूर्वक सेवा देने के बाद भी हमें न तो जॉब सिक्योरिटी मिली और न ही काम के अनुरूप वेतन। आज हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। डॉ. स्वाति और स्टाफ नर्स संध्या ने कहा- हम लोग उतना ही काम करते हैं, जितना एक परमानेंट कर्मचारी करता है। इसके बावजूद हमारा वेतन उनसे कम है। डॉ. स्वाति और स्टाफ नर्स संध्या ने कहा- हम लोग उतना ही काम करते हैं, जितना एक परमानेंट कर्मचारी करता है। इसके बावजूद हमारा वेतन उनसे कम है। पिपराईच CHC की स्टाफ नर्स संध्या ने कहा- 2008 से हम लोग उतना ही काम कर रहे हैं, जितना एक परमानेंट कर्मचारी करता है।

जिला महामंत्री बोले- कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया

NHM के जिला महामंत्री और संयोजक अशोक पांडेय ने बताया- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर शासन और प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन उचित समाधान नहीं मिलने से कर्मचारियों में असंतोष है। इसी को लेकर दो दिनों तक CMO कार्यालय में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेशभर के NHM स्वास्थ्यकर्मी 8 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में एकत्र होकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसमें गोरखपुर के सभी संविदा कर्मचारी भी शामिल होंगे।



NHM कर्मचारियों ने नारेबाजी की।

जिलाध्यक्ष बोले- परमानेंट कर्मियों की तरह हमें भी सुविधाएं मिलें

NHM के जिलाध्यक्ष रजनीश सिंह ने कहा- हमारी मांग है कि जिस तरह परमानेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसी तरह हम भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमें भी उनके समान वेतन दिया जाए। साथ ही जीवन बीमा, EPF और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं।

20 साल बाद ऐसे हालात, बस्ती में स्कूल में घुसा पानी, उन्नाव में एक की मौत

लखनऊ में लेटे हनुमानजी डूबे गर्भगृह में 13 फीट पानी

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी । यूपी में पहाड़ों पर हुई बारिश से 10 नदियां उफान पर हैं। लखनऊ और सीतापुर समेत 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर लगातार 8वें दिन बढ़ रहा है। फैजुल्लागंज इलाके के 40 हजार घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है।

लेटे हनुमानजी के गर्भगृह में करीब 13 फीट तक पानी भर गया है। लेटे हनुमानजी पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। 20 साल बाद पहली बार गर्भगृह को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया है। इधर, गोंडा में सरयू नदी का कटान तेज हो गया है। बस्ती में अटल



आवासीय विद्यालय परिसर में मनोरमा नदी का पानी घुस गया है। उन्नाव में दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई। सोमवार देर शाम 8 जिलों में आंधी-बारिश हुई। बाराबंकी, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में ओले गिरे। आंधी से सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। आज 33 जिलों में बारिश का अलर्ट है।

लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ के बीच नाव नहीं मिलने पर एक बुजुर्ग ने जुगाड़ से गद्दे की नाव बना ली। गद्दे के सहारे वे पानी पार करने की कोशिश करते नजर आए। लखनऊ में गोमती नदी के पानी से हनुमंत

> लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया- बिहार और यूपी के ऊपर बारिश का नया सिस्टम बना है। बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं आ रही हैं। इसलिए यूपी के मौसम में बदलाव आया है। अब एक हफ्ते तक बारिश की संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं।

धाम परिसर डूब गया है। वहीं लेटे हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पानी पहुंच गया है। लगभग 20 साल बाद गर्भगृह में पानी पहुंचा है।



मंदिर के गर्भगृह में 13 फीट पानी भरा

लखनऊ में लेटे हनुमान के गर्भगृह में पानी पूरी तरह भर गया है। गर्भगृह के अंदर करीब 13 फीट पानी है। 20 साल बाद पहली बार गर्भगृह को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बंद किया गया है।

मंदिर के ऊंचाई वाले हिस्से में हनुमान जी की चरण पादुका रख दी गई हैं। यहीं से श्रद्धालु दूर से दर्शन कर रहे हैं।

बस्ती में अटल आवासीय विद्यालय में घुसा पानी

बस्ती के हर्रैया तहसील के बसहवा स्थित अटल आवासीय विद्यालय परिसर में मनोरमा नदी और बारिश का पानी घुस गया है। इससे छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

2006 के बाद यह स्थिति दोबारा देखने को मिली है। जलस्तर बढ़ने से गोमती के किनारे बसे आसपास के इलाके में जलभराव हो गया है।

हवा की टंकी फटने से युवक का हाथ उड़ा

गोरखपुर में दूसरे का सिर फटा, चारों तरफ फैला खून

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर । गोरखपुर में मंगलवार को हवा की टंकी फटने से बड़ा हादसा हो गया। धमाका इतना तेज था कि एक युवक का हाथ शरीर से अलग होकर दूर जा गिरा, जबकि पास काम कर रहे दूसरे युवक के सिर में गंभीर चोट आई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबरा गए। मौके पर चीख-पुकार मच गई और सड़क पर खून बिखर गया।

हादसे में आनंद सिंह (40) और आशीष (25) गंभीर घायल हुए हैं। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना जंगल कौड़िया थाना क्षेत्र में हुई।

बलुआ निवासी आनंद सिंह घर पर ही धुलाई सेंटर चलाते हैं। वाहनों के टायरों में हवा भरने के लिए उन्होंने हवा की टंकी लगा रखी थी,



जिसमें जनरेटर से हवा भरी जाती थी। मंगलवार सुबह आनंद टंकी में हवा भर रहे थे। इसी दौरान वह दूसरे काम में व्यस्त हो गए।

कुछ देर बाद उन्हें टंकी से हवा निकलने की आवाज सुनाई दी। वह जनरेटर बंद करने पहुंचे ही थे कि तेज दबाव के कारण टंकी अचानक फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के लोग सहम गए। हादसे में आनंद सिंह और आशीष गंभीर घायल हो गए।

धमाके की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

ध्वस्तीकरण : 132 करोड़ मुआवजा दिया, 12 महीने तक एक्शन हुआ दिसंबर तक मिलेगी मॉडल रोड

काशी दालमंडी में 181 मकान-मस्जिद ध्वस्त

तमसा संकेत, एजेंसी

वाराणसी । वाराणसी में दालमंडी प्रोजेक्ट के तहत चिह्नित 181 मकानों का ध्वस्तीकरण हो चुका है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी ने बचे हुए 5-6 मकानों पर पोकलैंड और जेसीबी से कार्रवाई की। कुछ हिस्सों को मजदूरों ने घरों पर चढ़कर हाथ से भी तोड़ा।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के मुताबिक, अब दालमंडी में ध्वस्तीकरण के लिए कोई नया मकान नहीं बचा है। पहले से कार्रवाई वाले मकानों के चिह्नित हिस्सों को अलग कर उन्हें पूरी तरह जमींदोज किया जा रहा है। नवंबर की शुरुआत तक पूरा डिसमेंटलिंग कार्य खत्म करने का लक्ष्य है।

दालमंडी में मकानों के साथ 6 मस्जिदें भी प्रोजेक्ट की जद में आई थीं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार भवन और मस्जिदों के लिए





650 मीटर की सड़क होगी 60 फीट चौड़ी

दालमंडी की नई सड़क से चौक थाने तक करीब 650 मीटर लंबी सड़क को मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जाना है। प्रोजेक्ट के तहत सड़क की चौड़ाई करीब 60 फीट होगी। इसमें 30 फीट सड़क और दोनों तरफ 15-15 फीट की पटरी होगी। सड़क के नीचे बिजली, सीवर और पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाएगी।

करीब 191 करोड़ रुपए मुआवजे का आकलन किया गया था। इसमें से अब तक करीब 132 करोड़ रुपए प्रभावित लोगों को दिए जा चुके हैं। केके सिंह ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई लगातार चल रही थी। धारा 19 के प्रकाशन के बाद प्रभावित लोगों को मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। दालमंडी प्रोजेक्ट के लिए जुलाई 2025 में मकानों की नपाई कर 181 भवन चिह्नित किए गए थे। इसके बाद रजिस्ट्री और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हुई। 29 अक्टूबर 2025 से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी। पीडब्ल्यूडी के अभियंता केके सिंह ने बताया कि 172 मकान पूरी तरह जमींदोज किए जा चुके हैं। 5-6 मकानों का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा हटाया जा चुका है, जबकि बचे हुए 5-6 मकानों पर सोमवार को मशीनों और मजदूरों ने कार्रवाई की।

अब सीवर, पानी और अंडरग्राउंड बिजली का काम शुरू

दालमंडी में ध्वस्तीकरण के साथ ही सड़क निर्माण की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। चौक थाने की तरफ से गहरी सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और अंडरग्राउंड बिजली के तार बिछाने का काम शुरू किया गया है।

पीडब्ल्यूडी का लक्ष्य है कि काम इसी गति से चलता रहा तो दिसंबर तक नई सड़क तैयार कर आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी।

केके सिंह ने कहा कि दिसंबर तक सड़क को पब्लिक के लिए खोलना विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग को भी अहम बताया।

थप्पड़कांड के बाद 2 हजार से अधिक लोग सड़क पर

अंशुमान सिंह के समर्थन में आया क्षत्रिय समाज, दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर । गोरखपुर में सपा नेताओं के बीच थप्पड़ कांड अब जातिगत मोड़ लेता जा रहा है। पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के पक्ष में निषाद समाज के लामबंद होने के बाद अब क्षत्रिय समाज भी एकजुट होने लगा है। मंगलवार को बांसगांव में 2 हजार से अधिक लोग अंशुमान के समर्थन में आ गए। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। इसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति सिंह की ओर से एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मां की गई। ज्ञापन में कहा गया कि किसी भी मामले में पूरी सच्चाई सामने आने से पहले एकतरफा



कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जांच में यदि आरोप निराधार पाए जाते हैं तो अंशुमान सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग भी की गई। कार्यक्रम में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री राजवीर सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता कालिका सिंह, मंडल उपाध्यक्ष जेपी सिंह, मंडल महामंत्री इंद्रजीत सिंह और अजीत सिंह सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी रहे। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह बबलू, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष यशवंत सिंह, मंत्री विनय कुमार सिंह, मृत्युंजय सिंह, विकास सिंह, रत्नेश्वर सिंह राजू, देवेश सिंह, राजन सिंह राजपूत, सपा नेता सीपी सिंह, भानु प्रताप सिंह, गोरख सिंह, छात्र नेता अभय सिंह, विजय प्रताप सिंह रासु, शिव सिंह, जय सिंह मौजूद रहे।

सोमवार को बांसगांव में क्षत्रियों ने महापंचायत लगाई। 3 घंटे से अधिक समय तक यहां आपस में चर्चा हुई। सभी ने एक स्वर में अंशुमान सिंह को अपना समर्थन दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह बबलू के आह्वान पर बांसगांव कस्बे की सभी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया गया था।

गौहन्ना के बबुरहिया में चार जेसीबी और भारी पुलिस बल के बीच ढाई घंटे चला विरोध

कोर्ट का आदेश रहा बेअसर कब्जा दिलाने पहुंची जेसीबी



विरोध

बृजेंद्र वीर सिंह

तमसा संकेत, अंबेडकरनगर। अदालती आदेश के अनुपालन में कब्जा दिलाने के लिए मंगलवार को गौहन्ना के बबुरहिया गांव पहुंची न्यायिक टीम को एक बार फिर कार्रवाई पूरी किए बिना लौटना पड़ा। मौके पर चार जेसीबी, कई थानों की पुलिस और पीएसी के जवान मौजूद थे। जेसीबी से कार्रवाई शुरू होते ही महिलाओं और बच्चों ने मशीनों के आगे बैठकर विरोध शुरू कर दिया। करीब ढाई घंटे तक पुलिस उन्हें समझाती रही, लेकिन विरोध नहीं थमा। प्रशासनिक अधिकारियों की



यह कार्रवाई देवनारायण बनाम झिनकू आदि मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन यादवेंद्र सिंह के आदेश के अनुपालन में कराई जा रही थी। न्यायालय ने कोर्ट अमीन को सभी पक्षों को सूचना देकर मौके पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

गैरमौजूदगी के बीच आखिरकार कार्रवाई रोकनी पड़ी। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी नहीं थी। न्यायिक टीम ने इसे कार्रवाई में बड़ी बाधा बताया। कोर्ट अमीन ने प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। अमीन के अनुसार, न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराने के लिए केवल पुलिस बल पर्याप्त नहीं है। मौके पर प्रशासनिक तंत्र का सहयोग भी जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण पुलिस ने भी आगे की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पुलिस अधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने को कहा गया था। कार्रवाई में व्यवधान डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। डिक्रीदार के खर्च पर जेसीबी उपलब्ध कराने को भी कहा गया था। इसी आदेश के तहत मंगलवार को चार जेसीबी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। इसके बावजूद कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। मौके से मिली जानकारी के अनुसार कब्जा दिलाने की कार्रवाई पहले भी कई बार नहीं हो सकी है। शुरुआती विवरण में इसे आठवीं बार विफल बताया गया है, जबकि मौके की न्यायिक टीम की ओर से इसे नौवीं बार बताया गया। हालांकि दोनों स्थितियों में एक बात स्पष्ट है कि

जेसीबी आगे बढ़ी तो महिलाएं मशीनों के सामने बैठीं

न्यायालय के अमीन और कर्मचारी सभी पक्षों को सूचना देने के बाद कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे थे। अकबरपुर, भीटी, सम्मनपुर समेत अन्य थानों की पुलिस के साथ पीएसी भी लगाई गई थी। कार्रवाई के लिए चार जेसीबी मौके पर खड़ी थीं।

कब्जा खाली करने की चेतावनी के बाद जब जेसीबी शुरू हुई तो महिलाओं और बच्चों ने उसके आगे बैठकर विरोध किया। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने काफी देर तक उन्हें समझाने का प्रयास किया। पुलिस के समझाने के बावजूद महिलाएं वहां से नहीं हटीं।

करीब ढाई घंटे तक मौके पर स्थिति बनी रही। विरोध के कारण जेसीबी से आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी।

गोलपुर की जर्जर पुलिया बनी राह की बाधा गड्ढों में भर रहा पानी

बरियावन-किछौछा मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, बारिश में बढ़ जाती है परेशानी

तमसा संकेत, संवाददाता



अंबेडकरनगर। जलालपुर क्षेत्र में गोलपुर बाजार के पास बरियावन-किछौछा मार्ग पर बनी जर्जर पुलिया राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनी है। पुलिया से रोजाना बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। इसमें स्कूली बच्चे, पैदल राहगीर और वाहन चालक शामिल हैं।

पुलिया पर जगह-जगह करीब एक फीट तक गहरे गड्ढे हो गए हैं। बारिश के बाद इनमें पानी भर जाता है। इससे गड्ढों की गहराई दिखाई नहीं देती। पुलिया पर कीचड़ और जलभराव के कारण दोपहिया वाहन चालकों को अधिक परेशानी होती है। वाहन असंतुलित होने का खतरा बना रहता है।

स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया लंबे समय से खराब है। बरसात में स्थिति और बिगड़ जाती है। गोलपुर बाजार आने-जाने वाले लोगों के साथ आसपास के गांवों के लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।

समाजसेवी अनिल सिंह, व्यापारी अलीम खान, दिलीप, दिनेश राजभर, अंबिका यादव, सदाशिव वर्मा, लल्लन वर्मा, वेद प्रकाश मिश्रा, अवधेश पांडेय, महेंद्र वर्मा, श्याम पांडेय, मनमोहन मिश्रा और संग्राम राजभर समेत अन्य लोगों ने पुलिया की हालत सुधारने की मांग की। ग्रामीणों और व्यापारियों ने संबंधित विभाग से पुलिया की मरम्मत कराने, गड्ढों को भरवाने और जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि पुलिया की खराब हालत को देखते हुए समय रहते मरम्मत जरूरी है।

फास्ट न्यूज

मेहनत का मिला सम्मान

अंबेडकरनगर। महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बीएससी नर्सिंग आठवें सेमेस्टर की छात्रा सलोनी भारद्वाज को उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर 37 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। भूषण साइंस की ओर से प्रोत्साहन राशि का चेक देकर उन्हें सम्मानित किया गया।

सलोनी भारद्वाज ने ऑनलाइन भूषण साइंस कोचिंग में अध्ययन के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया।

सीवर लाइन ने रोकी जलालपुर की रफ्तार

जलालपुर (अंबेडकरनगर)। कोतवाली के सामने सीवर लाइन खराब होने से जलालपुर के मुख्य मार्ग पर दो दिन तक यातायात प्रभावित रहा। सड़क पर पानी जमा होने के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों, वाहन चालकों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सीवर लाइन खराब होने से सड़क पर पानी जमा हो गया था। इससे मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। धीरे-धीरे दोनों ओर वाहनों की कतार बढ़ती गई। जाम के कारण स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों को भी परेशानी हुई।

मिलने पहुंचे प्रेमी को परिजनों ने पकड़ा

जहांगीरगंज (अंबेडकरनगर)। थाना क्षेत्र के मगनपुर-महिमापुर-रुचनपुर गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने के बाद दोनों परिवार आमने-सामने आ गए। प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था। इसी दौरान दोनों के परिजनों को इसकी जानकारी हो गई। इसके बाद परिवारों के बीच बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्षों के बीच मामले को लेकर बातचीत हुई।

कांग्रेस का प्रदर्शन, मतदाता सूची से नाम हटाने पर उठाए सवाल

अंबेडकरनगर में कलेक्ट्रेट के सामने जुटे कार्यकर्ता

तमसा संकेत, संवाददाता



जिलाध्यक्ष बोले-नाम विलोपन से पहले हो पारदर्शी सत्यापन बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग

अंबेडकरनगर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और नाम विलोपन के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंबेडकर प्रतिमा के पास जुटे। कार्यकर्ताओं ने SIR के विरोध में नारेबाजी करते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव ने आरोप लगाया कि SIR के दौरान देशभर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटना केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। इससे उसके मतदान के अधिकार पर असर पड़ सकता है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि SIR के नाम पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। पार्टी ने मांग की कि नाम विलोपन से पहले पर्याप्त सत्यापन किया जाए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाए, ताकि पात्र मतदाता सूची से बाहर न हों। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई।

बसें खड़ी होते ही ओझल हो जाती हैं दुकानें, ग्राहकों की राह भी रुकती

तमसा संकेत, संवाददाता

अकबरपुर में दुकानों के सामने लंबे समय तक रोडवेज बसें खड़ी रहने से व्यापारियों की परेशानी, उचित पड़ाव तय करने की मांग



अंबेडकरनगर। अकबरपुर में दुकानों के सामने रोडवेज बसों का ठहराव व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि चालक बसें दुकान के ठीक सामने खड़ी कर देते हैं। बस के खड़े होते ही कई बार पूरी दुकान सामने से दिखाई नहीं देती।

व्यापारियों के मुताबिक दुकान के सामने बस खड़ी रहने से ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पाते। सड़क से गुजरने वाले लोगों को भी दुकान दिखाई नहीं देती। इससे ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित होती है और कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि समस्या तब ज्यादा बढ़ जाती है, जब बस लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़ी रहती है। बड़ी बस के पीछे दुकान का बोर्ड और सामने का हिस्सा तक दिखाई नहीं देता। ग्राहक सामान लेने के लिए रुकने के बजाय आगे निकल जाते हैं। कई बार एक साथ कई बसें खड़ी होने से दुकानों के सामने का हिस्सा और सड़क का कुछ भाग घिर जाता है। इससे राहगीरों को भी आवागमन में दिक्कत होती है। स्थानीय व्यापारियों ने संबंधित अधिकारियों से बसों के लिए निर्धारित पड़ाव तय करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बसों का ठहराव दुकानों के सामने न हो। इसके लिए उपयुक्त स्थान तय किया जाए, ताकि बसों का संचालन भी प्रभावित न हो और बाजार की दुकानों तक ग्राहकों की पहुंच बनी रहे।

व्यापारियों के अनुसार बसों के व्यवस्थित ठहराव से सड़क पर आवागमन और दुकानों के सामने की जगह दोनों बेहतर तरीके से संचालित हो सकेंगे।

गोहन्ना में मकान गिराने की नोटिस से प्रभावित परिवारों से मिला सुभासपा संगठन

जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में घर-घर पहुंचे पदाधिकारी

तमसा संकेत, संवाददाता



परिवारों को नियमानुसार मदद और प्रशासन तक आवाज पहुंचाने का भरोसा

अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र के गोहन्ना में मकान गिराए जाने की नोटिस से प्रभावित परिवारों के बीच मंगलवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के पदाधिकारी पहुंचे। पार्टी के अनुसार, करीब 18 गरीब परिवारों को मकान गिराए जाने की नोटिस मिली है। पदाधिकारियों ने परिवारों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और सहयोग का भरोसा दिलाया। जिलाध्यक्ष जगलाल राजभर के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गोहन्ना पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से उनकी समस्या जानी। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन नियमानुसार परिवारों की आवाज प्रशासन तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि किसी परिवार को अनावश्यक रूप से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सुभासपा पदाधिकारियों ने प्रशासन से मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने और प्रभावित परिवारों की समस्या का समाधान कराने की मांग की। पार्टी नेताओं ने कहा कि परिवारों की स्थिति को देखते हुए उनकी बात सुनी जानी चाहिए।

मौके पर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल, राष्ट्रीय सचिव सीपी निषाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेंद्र राजभर, प्रदेश महासचिव हरेंद्र राजभर, प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप राजभर, जिला कोषाध्यक्ष वीरेंद्र राजभर समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सेवा संकल्प अभियान के तहत अंबेडकरनगर में लगाए गए जागरूकता स्टाल

7810 घरों की छतों से बन रही 23 मेगावाट बिजली

परियोजना अधिकारी के अनुसार, जिले में अब तक 7,810 घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं। इनसे करीब 23 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

तमसा संकेत, संवाददाता



अंबेडकरनगर। जिले में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया गया है। सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर जागरूकता स्टाल लगाए गए। यहां लोगों को घरों की छत पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने और योजना के लाभ की जानकारी दी गई। अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने श्रीराम इंटरप्राइजेज और यूनीनेडा की ओर से लगाए गए स्टाल का उद्घाटन अधीक्षण अभियंता रजनीश श्रीवास्तव और परियोजना अधिकारी प्रवीण नाथ पांडेय ने किया। अधिकारियों ने लोगों को योजना की प्रक्रिया और सौर ऊर्जा के उपयोग से होने वाली बचत की जानकारी दी।

यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी प्रवीण नाथ पांडेय ने बताया कि पीएम सूर्यघर योजना से चार प्रमुख स्तरों पर लाभ मिलता है। घर की छत पर सोलर प्लांट लगाने से बिजली के बिल में बचत होती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होती है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। एक यूनिट बिजली को कोयले से पैदा करने पर करीब 850 ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन की संभावना रहती है। वहीं रूफटॉप सोलर लगाने से जमीन की जरूरत भी कम होती है। एक मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट जमीन पर लगाने के लिए करीब चार एकड़ भूमि की जरूरत होती है। अधिकारियों के अनुसार, इतनी क्षमता के सोलर प्लांट यदि जमीन पर लगाए जाते तो करीब 92 एकड़ भूमि की जरूरत होती। रूफटॉप सोलर से इतनी भूमि का उपयोग बच रहा है। स्टालों के माध्यम से नागरिकों को योजना की जानकारी देने के साथ रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रक्रिया समझाई गई।

भियांव में विशेष सचिव ने किया स्टाल का उद्घाटन

विकासखंड भियांव में यूनीनेडा के सहयोग से एलके पावर सिस्टम की ओर से जागरूकता स्टाल लगाया गया। इसका उद्घाटन विशेष सचिव कौशल विकास अभिषेक सिंह ने किया।

उन्होंने लोगों को घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने के लिए योजना की जानकारी लेने और इसका लाभ उठाने को कहा। स्टाल पर नागरिकों को सौर ऊर्जा से जुड़ी जानकारी दी गई।

10 महीने बाद पीड़ित के घर पहुंची मदद विधायक ने थामा महेंद्र सिंह का हाथ

अरिया बाजार में मकान ध्वस्तीकरण के बाद से परेशान परिवार से मिले राम अचल राजभर

तमसा संकेत, संवाददाता



अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरिया बाजार में मकान ध्वस्त होने के करीब 10 महीने बाद पीड़ित महेंद्र सिंह के घर मदद पहुंची। सपा विधायक राम अचल राजभर रविवार को उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मुलाकात कर उनकी स्थिति जानी और जरूरी सामान उपलब्ध कराया। विधायक ने पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर आवाज उठाने का भरोसा दिया। महेंद्र सिंह का आरोप है कि करीब 10 महीने पहले बुलडोजर लगाकर उनका मकान ध्वस्त कर दिया गया था। उनका कहना है कि जमीन को लेकर विवाद के बीच मकान गिराया गया। घटना के बाद से वह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के यहां शिकायत लेकर पहुंचते रहे। उनका कहना है कि अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल सका है। विधायक राम अचल राजभर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने परिवार की मौजूदा स्थिति भी जानी। इसके बाद जरूरी सामान उपलब्ध कराया। लंबे समय से परेशान परिवार के लिए यह मदद तत्काल राहत के रूप में सामने आई। महेंद्र सिंह ने विधायक को अपनी समस्या और अब तक की गई शिकायतों के बारे में बताया। विधायक ने मामले को आगे उठाने का भरोसा दिया। राम अचल राजभर ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए वह मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे। उन्होंने संबंधित स्तर पर मामले को रखने और पीड़ित परिवार की मदद जारी रखने की बात कही। करीब 10 महीने से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे महेंद्र सिंह के घर जनप्रतिनिधि के पहुंचने से परिवार को अपनी समस्या आगे उठाए जाने की उम्मीद जगी है।

महीनों से वेतन नहीं मिलने पर बी-पैक्स सचिवों ने सौंपा ज्ञापन

राजकीय सहायता से वेतन भुगतान की मांग

तमसा संकेत, संवाददाता



अंबेडकरनगर। बी-पैक्स पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग को लेकर मंगलवार को बी-पैक्स सचिव संघ ने प्रभारी एसडीएम राहुल गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष वशिष्ठ शुक्ला और सतिराम यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की गई। साधन समिति सचिव परिषद, उत्तर प्रदेश के लेटरपैड पर दिए ज्ञापन में कहा गया कि जिले की बी-पैक्स समितियों में कार्यरत कैडर सचिव, नॉन कैडर व प्रभारी सचिव, आंकिक, लिपिक, विक्रेता, सहयोगी और चौकीदारों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने राजकीय सहायता से वेतन भुगतान कराने की मांग की।

जिलाध्यक्ष वशिष्ठ शुक्ला ने कहा कि बी-पैक्स कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता और कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वेतन लंबित होने से कर्मचारियों के सामने आर्थिक परेशानी है। ज्ञापन में कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन भी वर्षों से लंबित होने का उल्लेख किया गया है। सचिव संघ ने चेतावनी दी कि मांगों के समाधान के लिए सात अक्तूबर को आयुक्त एवं निबंधक कार्यालय, लखनऊ में धरना दिया जाएगा। मांगें पूरी नहीं होने पर एक से पांच नवंबर तक कार्य बहिष्कार, तालाबंदी और सामूहिक त्यागपत्र जैसे कदम उठाने की बात कही गई है।

सुधार: भीटी, भियांव और टांडा में नोडल अधिकारियों ने परखी योजनाओं की हकीकत

गांव-गांव पहुंची शासन की नजर

तमसा संकेत, संवाददाता



नोडल अधिकारियों ने कहा कि आकांक्षी विकास खंडों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए योजनाओं की प्रगति का वास्तविक और अद्यतन आंकड़ों के आधार पर आकलन जरूरी है।

अंबेडकरनगर। आकांक्षी विकास खंडों में योजनाओं की प्रगति अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी। शासन से नामित नोडल अधिकारियों ने भीटी, भियांव और टांडा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति देखी। लाभार्थियों और ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर योजनाओं का वास्तविक लाभ भी जाना।

निरीक्षण के बाद विकास खंड मुख्यालयों पर समीक्षा बैठक हुई। इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी (बीडीएस) के तहत निर्धारित 50 इंडिकेटर्स की प्रगति देखी गई। विभागों की ओर से किए गए प्रयास और एक्शन प्वाइंट के निस्तारण की स्थिति भी जांची गई। नोडल अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों को चिन्हित कर प्राथमिकता से दूर करने के निर्देश दिए। सभी निर्धारित मानकों में सुधार के साथ योजनाओं का असर लाभार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। सर्किट हाउस सभागार में हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में 50 इंडिकेटर्स की बिंदुवार समीक्षा की गई। इनमें हेल्थ एवं न्यूट्रिशन के 17, एजुकेशन के 17, एग्रीकल्चर एवं एलाइड सर्विसेज के पांच, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पांच और सोशल डेवलपमेंट के छह इंडिकेटर्स शामिल हैं।

आकांक्षी ब्लॉकों में खुली विकास की पड़ताल

आंगनबाड़ी, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच

भीटी के नोडल अधिकारी निदेशक समाज कल्याण संजीव सिंह, भियांव के नोडल अधिकारी विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अभिषेक सिंह द्वितीय और टांडा के नोडल अधिकारी विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा टीके शिबू ने संबंधित विकास खंडों की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, रिसोर्स रिकवरी सेंटर (आरआरसी), स्वयं सहायता समूह केंद्र और अन्य विकास कार्यों की स्थिति देखी। ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली।

धुरिया समाज की बैठक को लेकर गोंड महासभा ने किया आगाह

तमसा संकेत, संवाददाता



प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गोंड बोले- 9 अक्तूबर की प्रस्तावित बैठक से समाज का कोई संबंध नहीं, एक मंच पर एकजुट रहने की अपील

अंबेडकरनगर। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा ने धुरिया समाज के नाम पर प्रस्तावित बैठक को लेकर समाज के लोगों को आगाह किया है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गोंड ने आरोप लगाया कि कुछ लोग समाज को संगठित करने के नाम पर भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने समाज के लोगों से ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की।

अजय कुमार गोंड ने बताया कि कुछ लोग नौ अक्तूबर को अंबेडकरनगर में सगा समाज की बैठक बुलाने की बात कह रहे हैं। उनका आरोप है कि बैठक के नाम पर समाज को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अलग-अलग राजनीतिक दलों और संगठनों के कार्यक्रमों में अपनी गतिविधियों के जरिए समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रामलगन गोंड एडवोकेट और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार गोंड ने संयुक्त बयान में कहा कि बैठक बुलाने वाले कुछ लोग पिछले 11 वर्षों से समाज को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबेडकरनगर में बैठक बुलाने वाला संगठन केवल तीन-चार लोगों तक सीमित है।

अजय कुमार गोंड ने कहा कि नौ अक्तूबर को विभिन्न दलों और संगठनों की ओर से कांशीराम की जयंती के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सम्पादकीय

महिला सुरक्षा का प्रश्न



सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह सही कहा कि अपराधी तत्वों के मन में इसका भय होना चाहिए कि वे कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे। उसकी ओर से यह टिप्पणी दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के संदर्भ में की गई। उसने यह भी कहा कि हर महिला को सुरक्षित महसूस करना चाहिए-चाहे वह रात में सड़क पर पैदल चल रही हो या मेट्रो और बस से यात्रा कर रही हो। यह स्थिति केवल दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं, पूरे देश में बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को कुछ सुझाव भी दिए। निःसंदेह पुलिस को सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उसे लोगों और विशेष रूप से महिलाओं का भरोसा जीतने की भी जरूरत है, ताकि वे अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं से उसे बेहिचक अवगत करा सकें। पुलिस को एक ओर जहां संवेदनशील बनना होगा, वहीं दूसरी ओर अपराधियों के प्रति और सख्त रवैया भी अपनाना होगा। यह रवैया हर किस्म के अपराधियों के प्रति अपनाने की आवश्यकता है। इसमें दोराय नहीं हो सकती कि पुलिस से महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के मामले में भी बहुत कुछ करने की अपेक्षा है। इसमें यह भी शामिल है कि वह अपनी जांच-पड़ताल में तेजी लाए, लेकिन ऐसी ही तेजी न्यायिक तंत्र को भी दिखानी होगी।

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अन्य अनेक मामलों की तरह महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मुकदमों में भी तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम रहता है। यदि कभी निचली अदालतों से समय रहते फैसला आ भी जाता है तो उच्चतर अदालतों में देर हो जाती है। जब न्याय में देरी होती है तो इससे अपराधी तत्वों को राहत तो मिलती ही है, समाज को सही संदेश भी नहीं जाता।

ऐसे भी उदाहरण हैं, जब कोई वर्षों जेल की सलाखों के पीछे पड़ा रहता है और बाद में वह निर्दोष पाया जाता है। यह अच्छी बात है कि गत दिवस गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नई न्याय संहिता के चलते निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में तीन वर्ष के भीतर फैसला होगा, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुलिस के साथ वकीलों और न्यायाधीशों को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। यह ठीक नहीं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध संबंधी कानून कठोर किए जाने के बाद भी ऐसे अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर पुलिस के साथ न्यायिक तंत्र, दोनों को ही विचार करना होगा। इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर समाज भी चेते। भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव समय की मांग है।

बेहतर विकल्प एवं जरूरी मुद्दों का अभाव ही विपक्ष की अक्षमता



भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि यहां कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती और कोई भी विपक्ष हमेशा के लिए विपक्ष नहीं रहता। सत्ता के लंबे कार्यकाल के बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के प्रति उकताहट पैदा होती है। लेकिन उकताहट और सत्ता परिवर्तन के बीच एक बड़ा अंतर है। मतदाता किसी सरकार से नाराज हो सकता है, उसके कामकाज पर सवाल उठा सकता है, फिर भी केवल नाराजगी के आधार पर किसी ऐसे विकल्प को स्वीकार नहीं करता, जिसके पास देश के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा न हो, जो सत्ता का लालची एवं बेहतर विकल्प से वंचित हो। आज भारतीय राजनीति में विपक्ष के सामने मूल प्रश्न यही है-क्या वह केवल सरकार से असंतुष्ट है या जनता के सामने कोई विश्वसनीय विकल्प भी रख रहा है? राहुल गांधी लंबे समय से यह सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के प्रति अपेक्षित एंटी-इंकंबेंसी दिखाई क्यों नहीं देती। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और 'वोट चोरी' के कारण जनता की वास्तविक इच्छा सामने नहीं आ पा रही। इन आरोपों के समर्थन में उनके द्वारा प्रस्तुत दावों को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है, उन्हें अंतिम रूप से सिद्ध तथ्य मानना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर उठने वाले प्रत्येक प्रश्न का निष्पक्ष और तथ्यात्मक उत्तर मिलना लोकतंत्र के हित में है। इसी संदर्भ में एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विवाद महत्वपूर्ण हो गया है। निर्वाचन आयोग स्वयं एसआईआर-2026 से संबंधित मतदाता सेवाएं और मतदाता सूची उपलब्ध करा रहा है तथा वह अपने को स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण बताता है। दूसरी ओर विपक्ष ने इस प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस विवाद को अब सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती मिली है। इस पूरे मामले का अंतिम निष्कर्ष राजनीतिक नारों से नहीं, संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया से निकलेगा। यहीं विपक्ष की राजनीति की असली परीक्षा शुरू होती है। चुनाव आयोग के विरुद्ध आंदोलन करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है। मतदाता सूची में यदि किसी पात्र नागरिक का नाम गलत ढंग से हटाया गया है तो उसका विरोध होना चाहिए। यदि किसी अधिकारी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा केवल आयोग के विरोध से नहीं होगी। लोकतंत्र की रक्षा तब होगी जब विपक्ष जनता को यह भी बताए कि सत्ता मिलने पर वह शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शहरी जीवन, कानून-व्यवस्था और प्रशासन में क्या बदलेगा। यही वह बिंदु है जहां 'वोट चोरी' का राजनीतिक विमर्श जनता के रोजमर्रा के सवालों से टकराता है। एक सामान्य परिवार को बच्चों की महंगी शिक्षा की चिंता है। रोजगार की बदलती प्रकृति, एआई और नई तकनीक के कारण पारंपरिक कौशल तेजी से अप्रासंगिक हो रहे हैं। डिग्री लेने के बाद भी रोजगार की गारंटी नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की घटनाएं युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाती हैं। ऐसे में युवा यह जानना चाहता है कि अगली सरकार परीक्षा व्यवस्था को कैसे विश्वसनीय बनाएगी, स्कूलों की गुणवत्ता कैसे सुधारेगी और बदलती तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए करोड़ों युवाओं को तैयार कैसे करेगी। किसान की समस्या भी केवल एमएसपी या आंदोलन तक सीमित नहीं है। फसल आने पर कीमत गिर जाती है और कुछ महीने बाद वही प्याज, टमाटर या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं। इसका समाधान केवल विरोध में नहीं, बल्कि गांव-कस्बे तक भंडारण, कोल्ड-चेन, प्रसंस्करण, कृषि बाजार और मूल्यवर्धन की मजबूत व्यवस्था में है। विपक्ष यदि कृषि सुधारों का विरोध करता है तो उसे यह भी बताना होगा कि वह वैकल्पिक कृषि ढांचा किस तरह खड़ा करेगा। केवल बड़े उद्योगपतियों पर राजनीतिक प्रहार या संपत्ति की गणना जैसे नारों से रोजगार पैदा नहीं होते। विपक्ष यदि संपत्ति के पुनर्वितरण या सामाजिक न्याय की बात करता है तो उसे साथ ही यह भी बताना होगा कि संपत्ति और अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। 'जितनी आबादी, उतना हक' जैसी राजनीति सामाजिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न को सामने लाती है, लेकिन आज की चुनौती प्रतिनिधित्व के साथ-साथ क्षमता निर्माण की भी है। पिछड़े, दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और अवसर मिलें-यह सामाजिक न्याय का अधिक स्थायी आधार है। केवल आंकड़े गिनना पर्याप्त नहीं, उन आंकड़ों के पीछे खड़े मनुष्य का जीवन बदलना जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में ममता बनर्जी की भूमिका विशेष चर्चा का विषय बनी है। राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर नया विमर्श अवश्य उभरा है। हाल की इंडिया गठबंधन की बैठक में उन्होंने विपक्ष का दायरा बढ़ाने और व्यापक एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा संकट केवल भाजपा से मुकाबला नहीं, बल्कि उसके भीतर का परस्पर अविश्वास है। सीटों का बंटवारा, क्षेत्रीय वर्चस्व, नेतृत्व का प्रश्न और राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर पर साथ आना आसान नहीं है। आज की स्थिति में आप का चुनाव आयोग तक प्रस्तावित मार्च से अलग रहकर अपना रास्ता अपनाना भी इस अंतर्विरोध को दिखाता है। कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, राजद, आप और दूसरे क्षेत्रीय दल जब अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राजनीति करते हैं, तब राष्ट्रीय मंच पर उनका साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या है? जनता इसी का उत्तर चाहती है। चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी यही कसौटी लागू होती है। इंडिया गठबंधन ने 6 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग तक मार्च सहित विरोध कार्यक्रम घोषित किए हैं और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। यह आंदोलन संवैधानिक प्रश्नों को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला सकता है। लेकिन यदि विपक्ष का पूरा राजनीतिक अभियान केवल एक व्यक्ति के इस्तीफे तक सीमित रह गया, तो इससे चुनावी संस्थाओं पर व्यापक विश्वास का प्रश्न हल नहीं होगा। उसे यह भी बताना होगा कि सत्ता में आने पर निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, मतदाता सूची, ईवीएम-वीवीपैट, चुनावी चंदे और चुनावी पारदर्शिता को लेकर वह कौन से संस्थागत सुधार करेगा। बड़ा प्रश्न है कि सत्ता की पात्रता को विकसित करने के लिये विपक्ष क्यों नहीं जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सकारात्मक राजनीति को बल देती।

- ललित गर्ग

> रोजगार का प्रश्न इससे भी बड़ा है। भारत की युवा आबादी को उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, अनुसंधान और नई तकनीक से जोड़ना होगा। निवेश के लिए स्थिर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासन और भरोसेमंद कारोबारी वातावरण जरूरी है।

भाजपा के शीर्ष ...

प्रदीप कुमार वर्मा

भाजपा ने सभी आठ नए उम्मीदवार उतारे, सपा ने भी युवा चेहरे पर जताया भरोसा

राज्यसभा का घमासान नए चेहरों को कमान

देश की राजनीति में अपना अलग मुकाम रखने वाले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का ₹काउंटडाउन₹ शुरू हो गया है। यूपी में राज्यसभा की दस सीटों के लिए सोलह अक्टूबर को चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए आगामी नवंबर माह में आठ भाजपा, एक बसपा और एक सपा की सीट खाली हो रही है। बसपा के पास सदस्य संख्या नहीं है। सपा विधायकों की संख्या के हिसाब से दो उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है। राज्यसभा चुनाव की कवायद में भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के लिहाज से दस सीटों वाले इस राज्यसभा चुनाव में ₹एक सीट₹ को लेकर भाजपा और सपा में राजनीतिक ₹रासाकसी₹ का दौर और चिंतन जारी है।

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम से एक बार फिर सबको चौंका दिया है। वही,सपा द्वारा देश के प्रमुख पूंजीपति को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद चर्चा अपने चरम पर है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए जारी अपनी लिस्ट में पिछड़ा



दलित अगड़ा पॉलिटिक्स के जरिए समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति को करारा जवाब दे दिया है। पार्टी ने 3 ओबीसी, 2 दलित, 2 ब्राह्मण और 1 ठाकुर समुदाय के प्रतिनिधि को टिकट दिया है। भाजपा की ओर से जारी लिस्ट में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्णा पाण्डेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार के नाम शामिल हैं। भाजपा की सूची में शामिल नामों के पीछे जहां क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश साफ नजर आ रही है। इसे अखिलेश यादव की रणनीति को सीएम योगी आदित्यनाथ के जवाब के तौर पर माना जा रहा है। वहीं, अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अलग-अलग वर्गों को संदेश देने की भी कोशिश की गई है। भाजपा की लिस्ट की एक और खासियत यह है कि पिछले कई दिनों से राज्यसभा की दौड़ में जितने बड़े-बड़े नाम लिए जा रहे थे। उनमें से शायद कोई इसमें शामिल नहीं है। यही नहीं इस लिस्ट में मौजूदा राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीएल वर्मा का नाम भी नहीं है। यानी दोनों को इस बार रिपीट नहीं किया गया है। इस बार यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया गया है। धर्मपाल सिंह योगी सरकार में पशुधन मंत्री है और बरेली की आंवला सीट से विधायक हैं। सपा ने एक सीट पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव और दूसरी पर पूंजीपति धनराज परिमल नाथवानी को टिकट दिया है। दोनों नामांकन भी कर चुके हैं। सपा की उम्मीदवारी पर राजनीतिक विरोधी हमलावर है, क्योंकि यह दोनों ही राज्यसभा प्रत्याशी सपा की विचारधारा पर फिट नहीं बैठते हैं। भाजपा, सपा पर इस बात को लेकर हमलावर है कि सपा के पीडीए में पी से परिवारवाद और पूंजीपति हो गया है। यही नहीं सपा के राजनीतिक विरोधी इस बात को भी लेकर हमलावर है कि राज्यसभा के लिए भेजे जाने वाले नाम में कोई भी दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग से नहीं है। देश के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सपा की पीडीए वाली थ्योरी में राजनीतिक स्वार्थ के हिसाब से बदलती रही है और पीडीए महज एक जुमला साबित हो रहा है। उप्र में राज्यसभा चुनाव में भाजपा और सपा के हार जीत के गणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि कुल 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में अभी 397 विधायक हैं तथा 6 सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए कुल 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोटो की आवश्यकता होती है। भाजपा के पास अपने सहयोगियों अपना दल एस, आरएलडी, सुभासपा, निषाद पार्टी आदि को मिलाकर लगभग 288 से 293 विधायक हैं। इसके आधार पर एनडीए की 7 सीटें पूरी तरह सुरक्षित हैं और 8वीं सीट के लिए उन्हें कुछ और वोटों या समर्थन की जरूरत होती है। वहीं,समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के पास लगभग 102 से 103 विधायक हैं, जिससे उनकी 2 सीटें आसानी से पक्की हो जाती हैं। इस गणेश से ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव जरूर रूप से संपन्न हो जाएगा।

प्रदेश में ...

शिखा अवस्थी/ओबैदुर रहमान

प्रदेश में संचालित एण्टी भू-माफिया अभियान से सार्वजनिक सम्पत्तियों की हुई सुरक्षा

सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा न केवल शासन और प्रशासन के लिए चुनौती है, बल्कि यह आमजन के अधिकारों तथा विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न करता है। सरकारी भूमि, ग्राम समाज की भूमि, तालाब, चारागाह, सड़क, नाली तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्तियों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराना सुशासन की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में एण्टी भू-माफिया अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है।

प्रदेश में सार्वजनिक सम्पत्तियों पर हुए अवैध कब्जों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 01 मई, 2017 द्वारा राज्य, मण्डल, जनपद एवं तहसील स्तर पर चार स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से अवैध कब्जों की पहचान, उनके विरुद्ध कार्रवाई तथा सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया गया है। अभियान को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के लिए एण्टी भू-माफिया पोर्टल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक अवैध कब्जे से सम्बन्धित अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं तथा शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति का अनुश्रवण भी किया जाता है। इससे शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता बढ़ी है और प्रशासनिक कार्रवाई की नियमित निगरानी संभव हुई है। दिनांक 09 सितम्बर, 2026 तक एण्टी भू-माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे से सम्बन्धित कुल 4,38,351 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 4,36,858 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 1,493 शिकायतें निस्तारण हेतु प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की दर लगभग 99.66 प्रतिशत है, जो अभियान के प्रभावी अनुश्रवण और त्वरित कार्रवाई को प्रदर्शित करता है। प्रदेश के चलाये गये इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। अब तक कुल 84,069.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया जा चुका है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सार्वजनिक सम्पत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

अवैध कब्जों के मामलों में केवल अतिक्रमण हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। इस अभियान के अन्तर्गत 25,120 राजस्व वाद, 1,168 सिविल वाद तथा 4,773 एफआईआर दर्ज करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त 1,377 अतिक्रमणकर्ताओं को भू-माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनमें से वर्तमान में 121 भू-माफिया जेल में निरुद्ध हैं। इस अभियान के अन्तर्गत अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध उनकी गतिविधियों और मामलों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न विधिक प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की गई है। 1,856 अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 69 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 03 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 70 के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट तथा 149 के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की गई है।

संतुलन जरूरी

वर्तमान में हम देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों ही परिवार की खुशहाली के लिए आवश्यक हैं। निष्कर्षतः लड़का और लड़की दोनों को एक समान समझना और उनके अधिकारों का सम्मान करना समाज की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। भेदभाव और असमानता को खत्म करके ही हम एक समृद्ध और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। भारत के अधिकांश घरों में माता- पिता अपने बुढ़ापे का सहारा बेटे को ही मानते हैं । उनकी बीमारी में दवाएं लाने वाला, रातों को जागकर सेवा करने वाला , उनके परिवार/रिश्तेदारों की जिम्मेदारी उठाने वाला और उनके जीवन की हर छोटी- बड़ी मुश्किल में साथ खड़ा रहने वाला अधिकतर बेटा या बेटे के परिवार ही होता हैं । यही सेवा और दायित्व- बोध वह अदृश्य उत्तरदायित्व हैं, जिसे समाज अक्सर स्वाभाविक मानकर अनदेखा कर देता हैं । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है। इसकी दो जातियां पाई जाती है लड़का और लड़की और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों की ही समान रूप से आवश्यकता है। लड़का और लड़की एक वाहन के दो पहिए है दोनों साथ मिलकर जीवन रूपी वाहन को चलाते हैं। यह दोनों ही एक समान है दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की सोच जो कि उन्हें समानता की दर्जा दे सकती है। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से ही लड़कियां अपनी सुझ बुझ और शक्ति का परीचय देती आई है। वह किसी भी तरह लड़को से कम नहीं है। लोगों की संकुचित सोच ने ही लड़कियों को लड़को से पीछे समझा हुआ हैं। जहां लड़की को देवी के रूप में मंदिर में पूजा जाता है वहीं घर और समाज में उस पर शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार भी किए जाते हैं। मध्य काल में पुरूषों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी जबकि लड़की सिर्फ घर में कैद होकर रहती थी। आधुनिक युग में लड़कियों ने अपने हक फिर से प्राप्त कर लिए हैं। वह हर क्षेत्र में लड़कों से भी आगे है। वह घर समाज और देश का नाम रोशन कर रही है। लड़कियों को किसी भी रूप में लड़को से कमजोर नहीं समझा जा सकता है।

> प्रदीप छाजेड़

जरा हटके

मत्स्य उत्पादन की ...

डॉ0 सीमा गुप्ता

बलरामपुर के मत्स्य पालकों को मिला वैश्विक मंच



प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और किसानों की आय में संवृद्धि के उद्देश्य से तराई अंचल के बलरामपुर जनपद में मत्स्य पालन क्षेत्र को एक संगठित और लाभदायक उद्योग के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस रणनीतिक पहल की गई है। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 'उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग' (यूपी एग्रीज) परियोजना तथा 'यूपी डास' के माध्यम से जनपद में आधुनिक मत्स्य पालन, वैज्ञानिक प्रबंधन और बहुस्तरीय बाजार संपर्कों को धरातल पर उतारा जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार और प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थान आईटीसी के मध्य हुए संस्थागत समन्वय से पारंपरिक मत्स्य पालकों को उन्नत कृषि-उद्यमियों के रूप में उन्नत करने की रूपरेखा पर कार्य किया जा रहा है। बलरामपुर जनपद की भौगोलिक स्थिति, प्रचुर जल संसाधन तथा प्राकृतिक आर्द्रभूमियाँ अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। अब तक स्थानीय स्तर पर सीमित संसाधनों, वैज्ञानिक ज्ञान के अभाव और केवल स्थानीय हाट-बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण मत्स्य पालक अपनी उपज का यथोचित मूल्य प्राप्त करने से वंचित रह जाते थे। इस नई पहल के माध्यम से जनपद के परंपरागत मत्स्य पालन तंत्र को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित कर स्थानीय उत्पादन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना की आधारशिला क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण पर रखी गई है, जिसके तहत बलरामपुर जनपद में कुल 11 विशिष्ट मत्स्य क्लस्टरों का गठन किया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर का समन्वित क्षेत्रफल लगभग 9 से 12 हेक्टेयर निर्धारित किया गया है, जिसमें 0.2 हेक्टेयर से लेकर 2.0 हेक्टेयर तक के तालाब धारक लघु एवं सीमांत मत्स्य पालकों को शामिल किया जा रहा है। व्यक्तिगत स्तर पर बिखरे हुए छोटे जलक्षेत्रों को एक संगठित क्लस्टर में पिरोने से आदान लागत (इनपुट कॉस्ट) में कमी, बड़े पैमाने पर उत्पादन और सामूहिक विपणन शक्ति का सीधा लाभ स्थानीय पालकों को प्राप्त होगा।

मत्स्य उत्पादन की उत्पादकता और गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए तकनीकी नवाचारों का व्यापक समावेश किया गया है। क्लस्टरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित एक्वाकल्चर प्रबंधन प्रणालियाँ तथा स्वचालित फीडिंग तकनीकें स्थापित की जा रही हैं। जल की गुणवत्ता, घुलित ऑक्सीजन (डीओ), पीएच मान, तापमान और अमोनिया स्तर की निरंतर निगरानी के लिए सेंसर आधारित डिजिटल प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल मछलियों की मृत्यु दर में भारी गिरावट आएगी, बल्कि वैज्ञानिक पोषण प्रबंधन के माध्यम से 'फीड कन्वर्जन रेशियो' (एफसीआर) में उल्लेखनीय सुधार संभव होगा।

योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों को उच्च गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज (फिंगरलिंग्स) और संतुलित प्रोटीनयुक्त मत्स्य आहार की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। प्रमाणित हैचरी के माध्यम से उन्नत भारतीय प्रमुख कार्प प्रजातियों जैसे रोहू, कतला, मृगल (नैनी) के साथ-साथ व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक मांग वाली पंगासियस और तिलापिया जैसी प्रजातियों के वैज्ञानिक संवर्धन पर बल दिया जा रहा है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तालाब निर्माण, जल शोधन, रोग नियंत्रण और जैव-सुरक्षा (बायो-सिक्योरिटी) मानकों के कड़े अनुपालन हेतु मत्स्य पालकों को व्यावहारिक और ऑन-फील्ड प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

ग्रामीण समाज के समावेशी विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस संपूर्ण क्लस्टर व्यवस्था में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (यूपीएसआरए-लएम) के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों को मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीकों, तालाब प्रबंधन, आहार वितरण तथा प्राथमिक ग्रेडिंग कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा रहा है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को केवल श्रम शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र कृषि-उद्यमी और निर्णयकर्ता के रूप में स्थापित कर उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगी। मत्स्य क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा उपज कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान (पोस्ट-हार्वेस्ट लॉस) की रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु परियोजना के तहत तालाब के किनारे से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक एक मजबूत और आधुनिक कोल्ड-चेन अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों, इंसुलेटेड एवं रेफ्रिजरेटेड परिवहन वाहनों, आधुनिक आइस-प्लांट्स तथा वैज्ञानिक भंडारण केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इससे मछली की ताजगी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और मत्स्य पालक औने-पौने दामों पर तत्काल बिक्री की विवशता से मुक्त हो सकेंगे। आईटीसी के वृहद लॉजिस्टिक्स और सप्लाई-चेन नेटवर्क के साथ एकीकरण इस पहल का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहलू है।

भतीजे आकाश को ससुर ने बिगाड़ा : मायावती

बयान

शादी से पहले कभी पार्टी से नहीं निकालना पड़ा, गलती का एहसास हुआ इसलिए वापस लिया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापस लेने के फैसले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा- आकाश आनंद को शादी से पहले कभी पार्टी से नहीं निकालना पड़ा। तब वे पार्टी में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

शादी के बाद ससुर अशोक सिद्धार्थ ने आकाश को बरगलाया। स्वार्थ के लिए आकाश की छवि खराब करने की कोशिश की। ऐसे में आकाश को सुधारने के लिए उन्हें कई बार पार्टी से अलग करना पड़ा। बाद में गलती का एहसास होने पर आकाश को माफ किया।

मायावती ने सोमवार को भतीजे आकाश को 31 दिन बाद BSP का राष्ट्रीय संयोजक बना दिया था। इससे पहले 3 सितंबर को उन्हें पद से हटाया था। मायावती अब तक 3 बार आकाश को पद से हटा चुकी हैं। हर बार उन्हें वापस पद दिया गया है।



एक दिन पहले ही मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेते हुए उन्हें पुरानी जिम्मेदारी सौंपी थी। 2 अक्टूबर को आकाश आनंद ने X पर मायावती को अपना राजनीतिक गुरु, प्रेरणा और रहबुआ मांद बताया था। उन्होंने लिखा था कि बसपा ही उनका परिवार है। वे किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने के फैसले का भी समर्थन किया था। 2017 में आकाश आनंद सहारनपुर की जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद वह लगातार पार्टी का काम कर रहे थे। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इसके बाद बसपा-सपा का गठबंधन टूट गया। उस वक्त यह बात सामने आई थी कि आकाश के कहने पर ही मायावती ने गठबंधन तोड़ा।

अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बाद अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी

मायावती ने कहा- मीडिया में यह बात बढ़ा-चढ़ाकर लिखी जा रही है कि आकाश को चार बार पार्टी से निकाला गया और फिर वापस लेकर राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। अगर मीडिया इस बारे में लिखता है तो उसे यह बताना चाहिए कि शादी से पहले कभी आकाश ने शिकायत का मौका नहीं दिया। बाद में पार्टी से अलग किए जाने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं।

उन्होंने कहा- अब जब अशोक सिद्धार्थ राजनीति से संन्यास ले चुके हैं तो ऐसी कोई स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए ताकि आकाश को फिर पार्टी से अलग करना पड़े। उम्मीद है कि आकाश अब राजनीति में आगे बढ़ेंगे।

> बसपा में वापसी के बाद आकाश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया। लिखा- आपने मुझे क्षमा किया और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी दोबारा सौंपी। इस भरोसे के लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। इसे मैं हल्के में कभी नहीं ले सकता। पिछले कुछ समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी सीख है कि यह मूवमेंट किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ा है।



आकाश आनंद ने 2017 में सक्रिय राजनीति में एंट्री ली थी।

2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आया था। आकाश ने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की पढ़ाई की है।

आबकारी विभाग राजस्व प्राप्ति में लगायी ऐतिहासिक छलांग

799.59 करोड़ रुपये अधिक राजस्व अर्जित

तमसा संकेत, संवाददाता

- सितम्बर, 2026 में 4,611.29 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित, विगत वर्ष इसी माह में प्राप्त राजस्व से 20.98 प्रतिशत अधिक
- अवैध शराब के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही में 59,530 अभियोग दर्ज, 16.18 लाख लीटर अवैध मदिरा/मादक द्रव्य बरामद, 9,522 व्यक्ति गिरफ्तार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों एवं अवैध शराब के कारोबार और माफिया तंत्र के खिलाफ अपनायी गयी जीरो टॉलरेन्स की नीति से आबकारी विभाग ने राजस्व प्राप्ति में नया कीर्तिमान बनाया है। विगत साढ़े चार वर्षों में विभाग ने राजस्व प्राप्ति और अवैध मदिरा के नियंत्रण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। संघन प्रवर्तन अभियान और सक्षम तकनीकी निगरानी से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर पूर्ण नियंत्रण लगाया गया। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के अर्धवार्षिक (अप्रैल से सितम्बर) में 29,406.50 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त किया, जो गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व 26,149.32 करोड़ रुपए के सापेक्ष 12.46 प्रतिशत अर्थात् 3,257.18 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं वित्तीय वर्ष 2026-27 के सितम्बर माह में 4,611.29 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के इसी माह में प्राप्त राजस्व 3,1811.70 करोड़ रुपए के सापेक्ष 20.98 प्रतिशत अर्थात् 799.59 करोड़ रुपए अधिक है।

फास्ट न्यूज

एटीएस अधिकारी बनकर बुजुर्ग से 34 लाख वसूले

लखनऊ। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने खुद को ATS अधिकारी बताकर एक बुजुर्ग को एक दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। आरोपियों ने उन्हें उनके नाम से आईसीआईसीआई बैंक खाते से आतंकी गतिविधियों के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग किए जाने का डर दिखाया। फैजुल्लागंज के रहने वाले केशव मुरारी गुप्ता (73) के साथ ठगी हुई है।

12 अक्टूबर तक पूरा होगा फसल क्षति का डिजिटल सर्वे

लखनऊ। योगी सरकार ने हाल में चक्रवात, अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए फसल क्षति का तेजी से और पारदर्शी आकलन कराने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों और अपर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए 12 अक्टूबर तक राहत पोर्टल पर डिजिटल क्रॉप सर्वे के अनुसार फसल क्षति की फीडिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पात्र किसानों को नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सेरेब्रल पाल्सी जागरूकता कार्यक्रम

लखनऊ । लखनऊ में विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के अवसर पर कीर्ति फाउंडेशन, लखनऊ द्वारा कल्याणपुर स्थित परिसर में सेरेब्रल पाल्सी (CP) से प्रभावित एवं अन्य विशेष बच्चों के लिए जागरूकता, स्वास्थ्य एवं उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष बच्चों की क्षमताओं को पहचानना एवं प्रोत्साहित करना, उनके अभिभावकों को चिकित्सकीय एवं पुनर्वास संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना तथा समाज में विशेष बच्चों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना था।

मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट एवं कॉल सेंटर के संचालन हेतु अधिकारियों का नामांकन



तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश ने जनपद लखनऊ में मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट के वाहनों के संचालन तथा कॉल सेंटर के संचालन का उत्तर-दायित्व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ को सौंपा गया है। एम0वी0यू0 पर तैनात पशु चिकित्सक, मल्टी टास्किंग पर्सनल एवं चालक सह सहायक कुल तीन सदस्य पूर्व की भांति अपना कार्य करते रहेंगे। लाभार्थियों का पूर्ण विवरण नियमित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराया जाएगा। एम0वी0यू0 वाहनों के पार्किंग स्टेशन भी यथावत बनाए रखे जाएंगे। उक्त कार्यों के सुचारू संचालन हेतु डॉ. हेमेन्द्र सिंह सोलंकी, उपमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) मोबाइल नंबर 8376003993, श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पशुधन प्रसार अधिकारी मुख्यालय मोबाइल नंबर 9450195814, श्री पियूष कुमार, मास्टर फ्लेयर मोबाइल नंबर 9415184493, श्री संजीव कुमार, अपर सांख्यकीय अधिकारी मुख्यालय मोबाइल नंबर 9415755696 तथा श्री अमित सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी मुख्यालय मोबाइल नंबर 8765829340 को नामित किया गया है।

लखनऊ एयरपोर्ट के लेबर कैंप में आग

घटना

प्लास्टिक से बने 17 कमरे जले, जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूदा मजदूर

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में बने लेबर कैंप में मंगलवार सुबह 6:30 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में तीन मंजिला बिल्डिंग जल गई। धुआं 2 किमी दूर से दिखाई दिया। तुरंत फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंचीं। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

दो मजदूर घायल हुए हैं। एक आग की चपेट में आने से झुलस गया, जबकि दूसरा दूसरी मंजिल से कूदने की वजह से चोटिल हुआ। जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह टर्मिनल से करीब 800 मीटर दूर है। इसे मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी तौर पर पीवीसी यानी प्लास्टिक से बनाया गया था।

यही वजह थी कि आग बहुत तेजी से फैली। हालांकि, हादसे से विमानों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट परिसर की इस बिल्डिंग में बिल्डिंग के प्रत्येक तल में 11 -11 कमरे (कुल 33) कमरे हैं। लेकिन जले सिर्फ 17 हैं। इसमें करीब 300 मजदूर रहते हैं। वे परिसर में एक होटल का निर्माण कर रहे हैं।



आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया।

स्टेशन फायर ऑफिसर (SFO) सुमित प्रताप सिंह ने बताया-बिहार के रहने वाले मजदूर निर्मल (30) आग की चपेट में आकर मामूली रूप से झुलस गया। वहीं, प्रतापगढ़ के रहने वाले राहुल कुमार (26) दूसरी मंजिल से कूदने से चोटिल हो गए। दोनों को कृष्णानगर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।



मजदूर बोले- सारा सामान जलकर राख हो गया

सीतापुर के रहने वाले रामपाल ने बताया- मैं नाइट ड्यूटी के बाद सो रहा था। इसी दौरान नीचे वाले फ्लोर पर आग लग गई। देखते ही देखते 15 कमरे जल गए। मैं ऊपर वाले कमरे में था, इसलिए किसी तरह जान बच गई। आग में कपड़े और पैसे जलकर राख हो गए। मूलचंद ने बताया- मैं एक हफ्ते से यहां काम कर रहा हूं। रात 3 बजे तक ड्यूटी की, फिर जाकर सो गया। इसके बाद शोर हुआ तो पता चला कि आग लग गई है। फिर जान बचाकर भागे। सामने रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।

बीजेपी के 8 प्रत्याशियों ने राज्यसभा का पर्चा भरा, भाजपाई से भिड़ा सुरक्षाकर्मी

प्रियंका रावत ने योगी के पैर छूकर नामांकन किया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । यूपी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के 8 प्रत्याशियों ने मंगलवार को नामांकन दाखिल कर दिया। बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका रावत, श्रुति गंगवार और गोपीकृष्ण पांडेय ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सबसे पहले धर्मपाल सिंह और सबसे आखिर में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की बेटी श्रुति गंगवार ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान भीड़ इतनी थी कि आपाधापी में विधानसभा के समिति कक्ष के दरवाजे के शीशे टूट गए। नामांकन के बाद एक भाजपा कार्यकर्ता की विधानसभा के सुरक्षाकर्मी से बहस हो गई। देखते ही देखते धक्का-मुक्की और गाली-गलौज होने लगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया। इसका वीडियो भी सामने आया है। सपा के राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मंगलवार को अखिलेश यादव ने तीसरा उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया। ऐसे में राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। पीयूष गोयल को पहले ही भाजपा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया जा चुका है। लिहाजा मोदी मंत्रिमंडल से तीन मंत्रियों को हटना तय है।



भाजपा के आठों राज्यसभा कैंडिडेट नए, इनमें 2 ब्राह्मण

यूपी भाजपा के सभी प्रत्याशी नए हैं। इनमें 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 3 पिछड़े और 2 दलित हैं। पिछड़े वर्ग में एक लोधी, एक कुर्मी और एक पाल समाज से हैं। वहीं, दलित वर्ग में एक खटीक और एक पासी समाज से हैं। पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल बीएल वर्मा और हरदीप सिंह पुरी का टिकट काट दिया। दिनेश शर्मा अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, सीमा द्विवेदी, बृजलाल, गीता शाक्य, अरुण सिंह को भी दोबारा मौका नहीं मिला।

मोदी मंत्रिमंडल से 3 मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना

लिस्ट में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री पुरी और राज्य मंत्री वर्मा का नाम नहीं है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी BJP ने दूसरे नाम घोषित किए हैं। यानी फिलहाल इन दोनों के लिए राज्यसभा में लौटने का रास्ता बंद हो गया है। पुरी के लिए अगला संभावित रास्ता 2027 में खाली होने वाली राज्यसभा सीटें हो सकती हैं। अप्रैल 2027 में केरलम की 3 सीटों का कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन वहां BJP के मौजूदा विधानसभा संख्या-बल को देखते हुए पुरी का वहां से राज्यसभा पहुंचना आसान नहीं माना जा सकता। पुरी का राज्यसभा कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को खत्म हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत वे लगातार 6 महीने तक ही सांसद बने बिना केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं।

> नामांकन के बाद भाजपा कार्यकर्ता की विधानसभा के सुरक्षाकर्मी से बहस हो गई। देखते ही देखते धक्का-मुक्की और गाली-गलौज होने लगी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया। इसका वीडियो भी सामने आया है।

राइफल से कुत्ते को गोली मारी बाइक रोककर उतरा

तमसा संकेत, एजेंसी



लखनऊ । लखनऊ में बाइक सवार युवक ने राइफल से कुत्ते को गोली मार दी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक बाइक रोककर नीचे उतरता है और कुत्ते पर फायर कर देता है। गोली लगते ही कुत्ता वहीं ढेर हो जाता है। मामला तालकटोरा इलाके की है। एक एनजीओ ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आसरा दी हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ की संचालिका चारु खरे ने बताया 6 सितंबर को सुबह करीब 6:30 बजे ग्रीन फील्ड स्कूल विशन ऑप्टिकल राजाजीपुरम के पास एक अज्ञात बाइक सवार गुजर रहा था। उसके पास राइफल थी। तभी कुत्ते भौंकने लगते हैं। गली के पास बाइक सवार अचानक रुकता है और राइफल निकाल कर कुत्ते को गोली मार दी। गोली लगने के कारण कुत्ते की मौत हो गई। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है।

घटना पास के एक घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में बाइक सवार नीली वर्दी पहने दिखाई दे रहा है। जिसके कंधे पर एक राइफल टंगी है। वह गुजरता है तभी कुछ कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं। इसको देखकर वह बाइक रोक लेता है और खड़ा हो जाता है, फिर अपनी जेब से गोली निकलता है। जिसे राइफल में डालता है फिर कुत्ते भोंकते हुए उसके दूसरी तरफ आते हैं। तभी एक कुत्ते पर फायर कर देता है। जिससे कुत्ता मौके पर ही मर जाता है। मामले में इंस्पेक्टर तालकटोरा कुलदीप दुबे का कहना है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

अनुरोध : दवाओं की मूल्य पारदर्शिता और ट्रेड मार्जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई का किया आग्रह

व्यापक जनहित में दवा कीमतों पर यूपीएफएसडीए का बड़ा कदम

- एनपीपीए को स्थानीय नियामकीय कार्रवाई की दी गई औपचारिक जानकारी, अस्पताल फार्मेसियों में मूल्य पारदर्शिता पर जोर
- अस्पताल फार्मेसियों में दवा की खरीद कीमत और मरीज से वसूली में 67 गुना तक अंतर मिलने के बाद विभाग ने उठाया बड़ा कदम

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ । मरीजों को दवाएं उचित कीमत पर उपलब्ध कराने और अस्पतालों में दवा मूल्य निर्धारण को पारदर्शी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (यूपीएफएस-डीए) ने राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की है। विभाग की आयुक्त एवं सचिव डॉ. रोशन जैकब ने नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) को पत्र भेजकर दवाओं की खरीद कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली कीमत के बीच बड़े अंतर की समस्या पर प्रभावी नियामकीय कार्रवाई का अनुरोध किया है।



उल्लेखनीय है कि यूपी एफएसडीए की ओर से प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्थित 22 मेडिकल कॉलेजों और 30 सरकारी एवं निजी अस्पतालों की 200 से अधिक फार्मेसियों में किए गए निरीक्षण में दवाओं, कंज्यूमेबल्स, मेडिकल डिवाइस और न्यूट्रास्यूटिकल्स की अस्पताल खरीद कीमत यानी प्राइस टू रिटेलर (पीटीआर) और मरीज से लिए जाने वाले मूल्य के बीच कई मामलों में बड़ा अंतर सामने आया। कुछ मामलों में यह अंतर 67 गुना तक पाया गया। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा एनपीपीए से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।

यूपीएफएसडीए की इस पहल का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि राज्य स्तर पर की गई स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई को राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया है।

हाई-एमआरपी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन कैपिंग और मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाने की सिफारिश

मरीज को मिले अस्पताल की खरीद का लाभ

यूपीएफएसडीए का मूल सवाल यही है कि यदि अस्पताल किसी दवा को निर्माता या सप्लायर से भारी छूट पर खरीद रहा है तो उस खरीद का लाभ मरीज तक किस हद तक पहुंच रहा है। वर्तमान व्यवस्था में पैकेजिंग पर एमआरपी अंकित होता है, जबकि अस्पतालों की संस्थागत खरीद में अक्सर इसबसे अधिक छूटश् के आधार पर सौदे किए जाते हैं। ऐसे में अस्पताल को मिलने वाली वास्तविक खरीद कीमत और मरीज से वसूली जाने वाली कीमत के बीच का अंतर मरीज के सामने स्पष्ट नहीं होता। विभाग ने एनपीपीए को बताया है कि ऐसी स्थिति में एमआरपी को अपेक्षाकृत ऊंचा रखने और उस पर बड़ी छूट देने की गुंजाइश बन सकती है। इससे कागज पर मरीज को एमआरपी माइनसश् के रूप में छूट दिखाई दे सकती है, लेकिन वास्तविक खरीद कीमत और मरीज से वसूले गए मूल्य के बीच का लाभ उसे नहीं मिल पाता।

नवंबर से अस्पताल फार्मेसियों में सार्वजनिक होगी दवाओं की खरीद-बिक्री कीमत

मरीजों के हित में अस्पताल फार्मेसियों को मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश

तमसा संकेत, संवाददाता

- यूपीएफएसडीए ने सभी रिटेल फार्मेसियों को पब्लिक वेबसाइट बनाने के निर्देश दिए, लाइसेंस, फार्मासिस्ट और साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी भी होगी ऑनलाइन'
- 1 नवंबर 2026 से व्यवस्था लागू करने की तैयारी
- नवरात्रि त्योहार के मद्देनजर व्यापारियों के हित में 11 अक्टूबर 2026 से नए थोक बिक्री लाइसेंस जारी किए जाने पर लगी रोक हटाने का निर्णय

लखनऊ। मरीजों को दवाओं की कीमतों को लेकर अधिक पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने सभी रिटेल फार्मेसियों को अपनी पब्लिक वेबसाइट तैयार करने और उस पर फार्मेसी से जुड़ी जरूरी सूचनाएं सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल परिसरों में संचालित फार्मेसियों को मरीजों के हित में दवाओं की खरीद दर और बिक्री दर के आधार पर मूल्य सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था का क्रियान्वयन 1 नवंबर 2026 से अपेक्षित है।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि पूर्व में जारी कार्यालय आदेश के तहत सभी रिटेल फार्मेसियों को अपनी एक सार्वजनिक वेबसाइट बनाते हुए उस पर लाइसेंस संख्या, नियुक्त फार्मासिस्ट, लाइसेंसी परिसर तथा स्टॉक संबंधी विवरण प्रदर्शित करना होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को साप्ताहिक रूप से अपडेट भी करना होगा।

विभाग ने अस्पतालों में संचालित फार्मेसियों को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। अस्पताल परिसर में स्थित ऐसी फार्मेसियां जहां मरीजों के पास दवाएं या अन्य चिकित्सा संबंधी उत्पाद खरीदने के लिए व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध नहीं होता, वहां मरीजों के हित में दवाओं की वास्तविक खरीद दर और बिक्री दर के आधार पर मूल्य सूची प्रदर्शित करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य दवाओं की कीमतों में पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि संबंधित दवा किस कीमत पर खरीदी गई और किस कीमत पर मरीज को उपलब्ध कराई जा रही है।

संजय यदुवंशी के परिवार से तीखी बहस

कॉमेडियन को पकड़ने आधी रात पहुंची सुल्तानपुर पुलिस

बहस

तमसा संकेत, एजेंसी

सुलतानपुर। सुल्तानपुर में अवधी गायक और कॉमेडियन संजय यदुवंशी को मारपीट के मामले में पकड़ने के लिए पुलिस सोमवार आधी रात उनके घर पहुंची। गेट पर ताला लगा था, तो पुलिसकर्मी दीवार फांदकर अंदर घुसे, लेकिन संजय घर पर नहीं मिले। इस दौरान उनके पिता, मां और भाई की पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई।

इसका वीडियो भी सामने आया है। SHO विपेंद्र कुमार वर्मा कह रहे हैं कि संजय चाहिए, तुरंत। इस



पर उनकी मां ने कहा- संजय यहां नहीं है। किसी के घर में रात में घुसने का अधिकार नहीं है। इस पर इंस्पेक्टर भड़क गए। बोले- एक इंस्पेक्टर की पावर समझते नहीं हो तुम। अभी तुम्हें तुम्हारा अधिकार बताता हूं। पूरा मामला धम्मौर थाना क्षेत्र के उघड़पुर गांव का है। संजय के परिवार ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। संजय ने कहा- पुलिस मुझे किस मामले में

संजय यदुवंशी ने एक्स पर लिखा- अगर एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया गया तो वह लखनऊ में धरना देंगे। रात 12 बजे धम्मौर थाने के एसएचओ शराब पीकर और दीवार कूदकर जांच कर रहे हैं। मेरे परिवार से गाली-गलौज कर रहे हैं। ऐसा कौन सा मुकदमा है मेरे ऊपर? किसकी हत्या या किसका अपहरण किया है?

इंस्पेक्टर बोला- मेरी पावर समझ नहीं रहे

सीओ बोले- जानलेवा हमले के मामले में दबिश देने पहुंची थी पुलिस

सीओ रितिक कपूर ने बताया कि थाना कोतवाली नगर में जफरुल हसन ने अपने बेटे शबीब रजा के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने का केस दर्ज कराया था। इसमें आरोपी संजय यदुवंशी फरार चल रहे हैं। इसी मामले की जांच के लिए पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। सोमवार देर रात उनके घर दबिश दी गई, लेकिन संजय नहीं मिले।

पिता बोले- इंस्पेक्टर ने कहा, संजय का एनकाउंटर करना है

संजय के पिता सियाराम यादव ने कहा- धम्मौर थाना प्रभारी 6 से अधिक पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे थे। घर का दरवाजा बंद था, तो पुलिसकर्मी गेट कूदकर अंदर पहुंचे। आवाज सुनकर पत्नी और बेटी की आंख खुल गई। पुलिसवालों को रोकने की कोशिश की तो बहस हो गई। इस दौरान इंस्पेक्टर ने पूछा कि संजय और मेरा दूसरा बेटा शिवा कहां हैं। मुझे उनका एनकाउंटर करना है। अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।

गिरफ्तार करना चाहती है? मेरी गिरफ्तारी का वारंट कहां है? हालांकि, सीओ ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, संजय के



सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ कॉमेडियन संजय यदुवंशी (फाइल फोटो)

खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। पहला- अंबेडकरनगर में 15 अगस्त के आसपास तिरंगे पर बैठने के आरोप में दर्ज हुआ था। दूसरा- धम्मौर थाने में 4 महीने पहले मारपीट का केस दर्ज हुआ था। तीसरा- बंधुआ कला थाना क्षेत्र में 6 महीने पहले कार टकराने को लेकर मारपीट हुई थी। इस मामले में संजय समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

सीएम ग्रिड के काम में देरी पर अल्टीमेटम दिया

नगर आयुक्त बोले- 4 दिन में काम पूरा करो

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर । कानपुर में चल रहे सीएम ग्रिड के काम में लापरवाही पर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को उन्होंने जोन-1 में ग्रीन पार्क चौराहे से परेड होते हुए घंटाघर तक सीएम ग्रिड सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रीन पार्क चौराहे के आसपास सड़क की खुदाई के कारण राहगीरों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताई।

उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को स्मार्ट सिटी के एलईडी लाइट और पोल को हटाते हुए 3 से 4 दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी कि तय समय में काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित संस्था को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

ग्रीन पार्क चौराहे से परेड चौराहे की ओर जाने वाली सड़क पर कई



दिनों से बड़ा गड्ढा खुदा मिला। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी की एलईडी लाइट और पोल लगे होने के कारण काम प्रभावित हो रहा है। नगर आयुक्त ने कार्यदायी संस्था मेसर्स कोनार्क एसोसिएट्स को निर्देश दिया कि अगले 3 से 4 दिन में एलईडी लाइट और पोल हटाकर काम पूरा किया जाए। उन्होंने मौके पर बैरिकेडिंग, नियमित सफाई और आम लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रीन पार्क से कृष्णा टावर की ओर जाने वाली सड़क पर किनारे बड़ा गड्ढा मिला।

फास्ट न्यूज

सरायन नदी का जलस्तर 60 सेमी घटा

सीतापुर । सीतापुर में शहर के बीच से गुजरने वाली सरायन नदी का जलस्तर पिछले तीन दिनों से लगातार घट रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे नदी का जलस्तर खतरे के निशान 131.00 मीटर से करीब 2.90 मीटर ऊपर 133.90 मीटर दर्ज किया गया। पिछले करीब 3 दिनों में जलस्तर में लगभग 60 सेंटीमीटर की कमी आई है। पानी घटने से कुछ इलाकों में घरों से जलभराव खत्म होने लगा है और राहत शिविरों में रह रहे लोगों की घर वापसी भी शुरू हो गई है।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में कार्यशाला

कानपुर । छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) कानपुर में रवाणी, व्यक्तित्व और व्यवसायर विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाभारत धारावाहिक के प्रसिद्ध सूत्रधार एवं प्रख्यात उद्घोषक हरीश भिमानी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने संवाद कला, युवाओं में व्यक्तित्व विकास और सामाजिक जीवन में वाणी के प्रभाव को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त दिया। हरीश भिमानी ने कहा कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रभावी संवाद, स्पष्ट उच्चारण और आत्मविश्वास बेहद आवश्यक हैं।

नवदुर्गा उत्सव जागरूकता अभियान

आगरा। आगरा के खंदौली क्षेत्र में सेव द एनवायरनमेंट की उत्तर प्रदेश राज्य इकाई की अध्यक्ष सुचेता हम्बीर सिंह ने जल, वायु और भूमि संरक्षण को लेकर नवदुर्गा उत्सव पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से प्राकृतिक संसाधनों नदी, तालाब और भूमि को रासायनिक सामग्री से दूषित न करने की अपील की।

थाईलैंड की महिला से शादी कर 60 लाख ऐंठा

टेनरी कारोबारी ने शादीशुदा होने की बात छिपाई

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर । कानपुर के चमड़ा कारोबारी ने थाईलैंड की महिला से धोखा देकर 2 साल पहले शादी की। फिर बिजनेस करने के नाम पर 60 लाख रुपए ठग लिए। जब पत्नी ने कारोबारी मोहम्मद इरफान से अपने रुपए वापस मांगे, तो इनकार करने लगा। कारोबारी थाईलैंड से कानपुर आ गया और पत्नी का फोन उठाना बंद कर दिया।

सोमवार को महिला उपसॉर्न पति की तलाश में लाटूश रोड स्थित उसके घर पहुंची। यहां उसे पता चला कि जिससे उसने शादी की है, वह पहले से शादीशुदा है। महिला ने बताया- बिजनेस के सिलसिले में थाईलैंड आने के दौरान मेरी मोहम्मद इरफान से मुलाकात हुई।

वहां हम दोनों 4 साल तक



रिलेशनशिप में रहे। 2 साल पहले हमने शादी कर ली। शादी के बाद इरफान हर 2 महीने में मुझसे मिलने थाईलैंड आता था। इस बीच उसने मुझसे रुपए ठग लिए। जब मैंने अपने रुपए वापस मांगे, तो उसने मुझसे थाईलैंड छोड़कर यहां रहने और धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखी। महिला ने मंगलवार को एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह से इस पूरे मामलेकी शिकायत की। पुलिस को अपनी शादी के फोटो समेत अन्य दस्तावेज भी सौंपे। मामले की जांच एसीपी अनवरगंज मंजय सिंह को सौंपी गई। एडीसीपी ने बताया कि महिला की शिकायत पर एफआई-आर दर्ज की गई है। इरफान को हिरासत में लिया गया है।

इनमें कारोबारी, 2 बहनें, भांजी मुजफ्फरनगर में डंपर से टकरा हाईवे से नीचे गिरी स्कॉर्पियो

बर्थडे से लौट रहे परिवार के चार लोगों की मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

मुजफ्फरनगर। यूपी के मुजफ्फर-नगर में कारोबारी, उनकी 2 बहनों और भांजी की सड़क हादसे में मौत हो गई। मां, पत्नी और दूसरी भांजी की हालत गंभीर है। कारोबारी हरिद्वार में अपने मौसा का 75वां जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रहे डंपर ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी।

इसके बाद स्कॉर्पियो बेकाबू होकर हाईवे से करीब 20 फीट नीचे गिर गई। डंपर भी पलट गया। ड्राइवर कूदकर भाग गया। हादसा सोमवार रात 11 बजे जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर पुरकाजी थाना क्षेत्र में हुआ। चीख-पुकार सुनकर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने स्कॉर्पियो का दरवाजा



हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे। शव देखकर परिजन एक-दूसरे से लिपटकर रोने लगे।

तोड़कर सभी को बाहर निकाला और सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान कारोबारी आदेश गोयल (45) उनकी बहनों में निशा (36) राखी (30) और निशा की 14 साल की बेटी श्रद्धा के रूप में हुई है। हादसे में आदेश की मां कुसुम देवी (65), पत्नी रूबी और राखी की बेटी वैष्णवी घायल हैं।



कारोबारी के बेटे की 25 नवंबर को शादी

आदेश के बेटे तुषार की 25 नवंबर को शादी तय है। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थीं। उनका दूसरा बेटा रचित (22) बेंगलुरु में रहकर LLB की पढ़ाई कर रहा है। बहन निशा गृहिणी थीं। उनकी शादी सहारनपुर के बेहट अड्डा निवासी राहुल सिंघल से हुई थी। उनके पति एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। उनका एक बेटा है।

आदेश गोयल जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर हरीनगर मोहल्ले के रहने वाले थे। वह स्क्रैप के कारोबार के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। सोमवार को वह पत्नी रूबी, मां कुसुम देवी, बहन निशा, उसकी 14 साल की बेटी श्रद्धा, छोटी बहन राखी और उसकी 7 साल की बेटी वैष्णवी के साथ

चीख-पुकार सुनकर राहगीर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। हादसे के बाद खेत में पानी भरा होने के कारण पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हुई। पुलिसकर्मी ग्रामीणों के साथ खाई में उतरे। करीब 30-35 मिनट तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को बाहर निकाला।

स्कॉर्पियो से हरिद्वार गए थे।

परिवार के लोग वहां मौसा राधेश्याम के 75वें जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सोमवार रात करीब 11 बजे सभी मुजफ्फरनगर लौट रहे थे। पुरकाजी-लक्सर स्टेट हाईवे पर सोलानी नदी पुल के पास उनकी स्कॉर्पियो डंपर से टकरा गई। इसके बाद स्कॉर्पियो पलटती हुई हाईवे से नीचे खेत में जा गिरी।

मिर्जापुर में गांव वाले भी नाराज हुए, वन विभाग बोला- जमीन तो हमारी है

दिव्या-मित्तल ने जिस स्कूल का मुद्दा उठाया, उसका काम रुका

तमसा संकेत, एजेंसी

मिर्जापुर । मिर्जापुर में पूर्व IAS दिव्या मित्तल की परमिशन से बन रहे स्कूल के निर्माण पर विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग ने इस जमीन पर दावा करते हुए 4 अक्टूबर की दोपहर को काम रुकवा दिया। लहुरियादह गांव में बन रहे स्कूल का काम रोके जाने से गांववाले नाराज हैं। वन विभाग के अफसरों ने कहा कि हलिया क्षेत्र में हमारे विभाग की जमीन पर स्कूल निर्माण गैरकानूनी है। वन विभाग की टीम नींव की भराई का काम कर रहे मिस्त्री, लेबरों का फावड़ा, तगाड़ी समेत सारा सामान भी ले गई।

इससे पहले 30 सितंबर को बीईओ हलिया प्रकाश चंद्र यादव



और ग्राम प्रशासक कौशलेंद्र गुप्ता टीम के साथ लहुरि-यादह गांव पहुंचे थे। यहां स्कूल के लिए जमीन की नपाई के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया था। लेकिन पांचवें दिन ही वन विभाग ने स्कूल का काम बंद करा दिया। रेंजर के मुताबिक, वन विभाग के मानचित्र में अराजी नंबर 730 और 732 में स्कूल का निर्माण कराया जा रहा था। 1359 फसली के वन विभाग के नक्शे में अराजी नंबर 733 राजस्व विभाग की जमीन है। इसी जमीन पर स्कूल बनवाया जा सकता है।

रेंजर का आरोप है कि स्कूल के जमीन आवंटित करते समय राजस्व विभाग की टीम ने वन विभाग से

गांववाले बोले- स्कूल बनवाने से पहले जांच करानी चाहिए थी

ग्रामीण हीरा यादव, चौरसिया देवी, राजकुमार और हरिलाल समेत अन्य लोगों का कहना है कि अगर जमीन वन विभाग की थी तो तहसील प्रशासन ने उसे स्कूल निर्माण के लिए आवंटित कैसे कर दिया? ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

कोई संपर्क नहीं किया। वन भूमि पर स्कूल के लिए जमीन आवंटित कर दी। वहीं, नाराज ग्रामीणों का कहना है कि उस जमीन पर तो पेड़-पौधे तक नहीं।



वन विभाग ने जब स्कूल का काम रुकवाया, उस समय जेसीबी से नींव की खुदाई चल रही थी।

लेखपाल बोले- ग्राम सभा की जमीन पर बन रहा स्कूल

स्कूल के लिए आवंटित जमीन को लेकर राजस्व और वन विभाग के दावे अलग-अलग हैं। लेखपाल निखिल पाठक के मुताबिक, अराजी नंबर- 1116 ग, रकबा 0.169 हेक्टेयर यानी करीब 13 बिस्वा जमीन आवंटित की गई है। यह जमीन ग्राम सभा और राजस्व विभाग की है। लेखपाल ने बताया, इसके बावजूद वन विभाग इस जमीन पर अपना दावा कर रहा। मामले की जानकारी सीनियर अफसरों को दी गई है। वहीं, ड्रमंडगंज रेंजर रविशंकर शर्मा का कहना है कि लहुरि-यादह गांव में जिस जमीन पर उच्च प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा था, वह वन विभाग की भूमि है। इस वजह से निर्माण काम रुकवाया गया है।

यूपीआई पर एमडीआर शुल्क के विरोध में हनुमान चालीसा

सरकार को सद्बुद्धि देने और शुल्क वापस लेने की मांग

तमसा संकेत, एजेंसी

कानपुर । यूपीआई पर पर्सन-टु-मर्चेंट (P2M) लेनदेन में प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क के विरोध में व्यापारियों ने मंगलवार को प्रदेशव्यापी अभियान चलाया। इसके तहत किदवईनगर संकटमोचन हनुमान मंदिर में व्यापारियों ने सामूहिक रूप से 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया।

इसके बाद हाथों में पोस्टर लेकर UPI पर MDR शुल्क मंजूर नहीं-मंजूर नहीं" के नारे लगाए और शुल्क वापस लेने की मांग की। सिर्फ कानपुर ही नहीं, यूपी के 50 जिलों के व्यापारियों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और एमडीआर शुल्क वापस लेने की सरकार से मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि 15 अक्टूबर से 2 हजार से अधिक के P2M-UPI लेनदेन



पर 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क लगाए जाने की प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में चिंता है। उन्होंने कहा कि MDR पर 18 प्रतिशत GST जुड़ने से प्रभावी शुल्क 0.472 प्रतिशत हो जाएगा। उनके मुताबिक इससे व्यापारियों की लागत बढ़ सकती है और खासकर कम मार्जिन वाले कारोबार पर असर पड़ सकता है। मिश्र ने कहा कि UPI और डिजिटल भुगतान अब व्यापारिक लेनदेन का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क से व्यापारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है।

पृष्ठ 01 का शेष...

'हमारे देश के साथ ...

कांग्रेस सूत्र का कहना है कि दोनों चुनाव आयुक्तों समेत मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाक़ात का समय लेने के लिए कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर चिट्ठी भेजी है. चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिकारी आ कर यदि आने वाले एक-दो दिनों में मुलाक़ात का भरोसा दे तो राहुल गांधी आज का अपना धरना खत्म कर सकते हैं. हालांकि राहुल गांधी की शर्त यही है मुलाक़ात सभी तीन सौ सांसद करेंगे. अब तक कांग्रेस की इस मांग पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने यदि मुलाकात का समय भी दिया तो वह शायद इतनी बड़ी संख्या में सांसदों से मुलाकात से इनकार कर दे.

इस बीच कांग्रेस मामले को लंबा खींचने और इसके आधार पर ही अपनी सियासी जमीन पुख्ता करने की कोशिश में है. 1 नबंवर को इंडिया गठबंधन की रैली के लिए रामलीला मैदान बुक हो गया है. राष्ट्रपति से मिलने के लिए कल या परसों 7 -8 अक्टूबर का समय मांगा गया है.अगर 9 अक्टूबर को समय मिला तो चलेगा. राष्ट्रपति से मिलने वालों में दोनों सदन के नेता प्रतिपक्ष यानि खरगे और राहुल गांधी,ममता बनर्जी,अखिलेश यादव,शरद पवार,उमर अब्बदुल्ला,तेजस्वी यादव,एमए बेबी और डी राजा(सीपीआई)के नाम हैं.

बुधवार का दिन दिल्ली में अहम हो सकता है. कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाने की जिद ठानी है तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी. इसका ऐलान सौरभ भारद्वाज ने किया है. भारद्वाज ने कहा कि 'आप', कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के नेता व कार्यकर्ता दोपहर एक बजे कश्मीरी गेट में जुटेंगे. उन्होंने कहा कि AAP ने पहले ही सड़क पर होने वाले सभी प्रदर्शन में शामिल होने का एलान किया था.

बंगाल, असम...

जिन सीटों पर वोटिंग हुई, उनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम, पुडुचेरी की थट्टानचावडी विधानसभा सीट और असम की नगांव लोकसभा सीट शामिल हैं। सभी सीटों के नतीजे 9 अक्टूबर को आएंगे।

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की वोटिंग मंगलवार शाम 6 बजे खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी भी लाइन में हैं, उन्हें वोट डालने दिया जाएगा।

चुनाव आयोग के मुताबिक, इन दोनों सीटों पर लगभग 79 प्रतिशत वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अधिकारी ने बताया कि वोटिंग शांतिपूर्ण रही और कुछ ही अप्रिय घटनाओं की खबर मिली।

पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में 79.39 प्रतिशत वोटिंग हुई, जबकि मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में शाम 5 बजे तक 78.42 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।

असम के जागीरोड...

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मुताबिक, इस साल दिसंबर या 2027 जनवरी में PM मोदी इस प्लांट का आधिकारिक उद्घाटन कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर फैब के बाद यह दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी होगी।

यह प्लांट जहां बना है, वहां जंगली हाथियों के झुंड घूमते हैं। सेमीकंडक्टर उत्पादन में नैनोमीटर स्तर की सटीकता जरूरी है। हाथियों का भारी कदम इतना वाइब्रेशन पैदा कर सकता है कि चिप असेंबली मशीनों में गड़बड़ी हो जाए।

इससे बचाने के लिए प्लांट के चारों ओर ग्रीन बेल्ट और रोडसाइड कंक्रीट, स्टील की मजबूत 'एलिफेंट-प्रूफ' दीवार बनाई गई है। सांपों से बचाव के लिए स्नेक रेस्क्यू टीम के अलावा वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी गई है। असम में तैयार हो रहे सेमीकंडक्टर प्लांट में दूसरे देशों में काम कर रहे असमिया युवा खास रुचि ले रहे हैं। कई हाई-स्किल्ड युवा प्रोफेशनल्स ने विदेश की नौकरी छोड़कर असम लौटने का फैसला किया है। कई के इंटरव्यू हो चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट में 3...

इसके बाद उन्होंने करीब 21 सालों तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में दीवानी, रिट और वाणिज्यिक मामलों से संबंधित मामले देखे।

उन्हें 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। 6 अगस्त 2013 को चीफ जस्टिस के रूप में प्रमोट हुई थीं। 5 जुलाई 2023 को उनका ट्रांसफर गुजरात हाईकोर्ट में हुआ था। जस्टिस सुनीता अग्रवाल लगभग 5 साल के कार्यकाल के बाद सुप्रीम कोर्ट से 29 अप्रैल, 2031 को रिटायर होंगी।

जस्टिस उपाध्याय का जन्म 16 जून 1965 को उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर जिले के मुस्कराई गांव में हुआ। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री।

वकील के रूप में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दीवानी और संवैधानिक मामलों में वकालत की। उन्हें 21 नवंबर 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया था। 28 मार्च 2023 को लखनऊ पीठ के चीफ जस्टिस और 29 जुलाई 2023 को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। इसके बाद 21 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी। उपाध्याय 15 जून, 2030 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे।

'पिछले 9.5 साल में...

HCL के संस्थापक शिव नादर ने इसी उत्तर प्रदेश से कंपनी की यात्रा शुरू की थी। आज यह यात्रा यूपी की धरती से निकलकर वैश्विक पहचान बना चुकी है। दस साल पहले शिव नादर ने लखनऊ में इस यात्रा को नई पहचान देने का संकल्प लिया था। आज उसी संकल्प के 10वें स्थापना दिवस के मौके पर हम इस कैंपस में एकत्र हुए हैं। HCL ने लखनऊ को चुना और लखनऊ ने HCL को अपनाया। दोनों की साझा यात्रा पर आज उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति गौरव महसूस कर सकता है।

सीएम ने कहा- इस कैंपस की सफलता के पीछे कर्मचारियों की मेहनत के साथ उनके परिवारों की दुआ और सपने भी जुड़े हैं। आज जब यूपी का युवा यहीं रहकर दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बना रहा है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके माता-पिता को होती है। दस साल पहले यूपी का युवा अच्छी डिग्री लेने के बाद करियर के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाता था। आज स्थिति बदल गई है। यूपी का युवा करियर के लिए लखनऊ को चुन रहा है और दुनिया का युवा भी लखनऊ आ रहा है। उन्होंने HCL कर्मचारियों से कहा कि वे सिर्फ कंपनी के कर्मचारी नहीं, बल्कि अब यूपी के ब्रांड एंबेसडर भी हैं।

सीएम ने कहा- सीएम ने कहा कि एक समय यूपी में बिजली की सुविधा भी कुछ परिवारों तक सीमित थी। आज यूपी बदल चुका है। अब प्रदेश में पहचान, रोजगार और नौकरी का संकट नहीं है। साढ़े नौ साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।

वायुसेना के नए ...

विमान में लगे नए रडार, मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कोऑर्डिने-शन को परखते हैं। किसी भी विमान को वायुसेना के बेड़े में शामिल करने के लिए हरी झंडी देते हैं।

वायुसेना में सैकड़ों घंटे उड़ान का अनुभव रखने वाले सीनियर पायलट को ही टेस्ट पायलट बनाया जाता है। इसके लिए एयरोस्पेस इंजीनियरिंग या साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथ्स की समझ जरूरी है। इसकी परीक्षा में पायलट को वह विमान उड़ाने दिए जाते हैं, जो उसने पहले कभी न छुए हों। इन्हें वायुसेना का टॉप गन माना जाता है, क्योंकि ये रिस्क जोन में काम करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के...

माओवादी आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई और पूर्वोत्तर में शांति प्रयास भी इनमें शामिल हैं। प्रस्ताव में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न मतभेदों के बावजूद सहयोग स्थापित करने की क्षमता से जोड़ा गया है।

उनकी अगुआई में भारत ने पहली बार महिला वर्ल्डकप जीता, स्मृति हो सकती हैं अगली कप्तान

हरमनप्रीत ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ी

सम्मान

नई दिल्ली, एजेंसी

हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। हरमनप्रीत की जगह स्मृति मंधाना टीम की नई कप्तान बन सकती हैं।

37 साल की हरमनप्रीत के नाम कई रिकॉर्ड हैं। इनमें बतौर कप्तान भारत को पहला महिला वर्ल्ड कप जिताना शामिल है। उनकी कप्तानी में टीम ने 2012, 2016, 2022 और 2026 एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया। 2012 एशिया कप में हरमनप्रीत ने सिर्फ फाइनल में कप्तानी की थी। बाकी मैचों में मिताली राज ने टीम की कमान संभाली थी। हरमनप्रीत ने लिखा, आज मैं सभी फॉर्मेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रही हूं। यह आसान फैसला नहीं है। इसमें सालों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल जुड़े हैं, जो जिंदगीभर मेरे साथ रहेंगे।

भारत ने 2025 में पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता। हरमनप्रीत वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कप्तान बनीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नाबाद 171 रन की पारी खेली। यह महिला वर्ल्ड कप की यादगार पारियों में शामिल है। 2018 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में शतक लगाया। ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं।

हरमनप्रीत 200 इंटरनेशनल टी-20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हैं। फरवरी 2026 में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनीं। उन्होंने 382 मैच खेले हैं। 150 T20I में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर। सितंबर 2026 में रिकॉर्ड बनाया।



हरमनप्रीत ने भारत के लिए 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे से इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने 8 टेस्ट, 164 वनडे और 210 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।



लगातार 2 बार एशियन गेम्स के गोल्ड जीते

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में लगातार दो गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने 2022 हांगझोउ एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर पहला गोल्ड जीता था। इसके बाद 2026 नागोया एशियन गेम्स में भी टीम ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

स्मृति पहले भी कप्तानी कर चुकीं

स्मृति मंधाना को हरमनप्रीत कौर के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिल सकती है। स्मृति पहले भी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं।

पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन नवाज का पुराना वीडियो वायरल

कहा था- भारत के हर गेंदबाज से नफरत है





नई दिल्ली, एजेंसी

एशियन गेम्स फाइनल में भारत के खिलाफ 96 रन बनाने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन नवाज का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वे कहते हैं कि उन्हें भारत के हर गेंदबाज से नफरत है।

वीडियो में जब एंकर उनसे पूछते हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा गेंदबाज है, जिसे वह मैदान पर आते ही निशाना बनाना चाहते हैं। इस पर वे हर भारतीय गेंदबाज का नाम लेते हैं। जापान में एशियन गेम्स का मेंस क्रिकेट फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था। भारत ने 19 रन से पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था।

हसन नवाज का यह बयान एशियन गेम्स के पहले का है। उनका यह पुराना इंटरव्यू अप्रैल 2026 में सामने आया था।

भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 211 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 61 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा 51 रन बनाकर नाबाद रहे। 212 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 192 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के लिए नवाज ने 51 गेंद में 96 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल रहे।

वर्ल्डकप जिताने वाले सूर्या को रणजी में भी जगह नहीं

मुंबई ने टीम का ऐलान किया, आयुष म्हात्रे उपकप्तान

नई दिल्ली, एजेंसी

टी-20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को रणजी ट्रॉफी के ओपनिंग मैच के लिए मुंबई टीम में जगह नहीं मिली है। 42 बार की चैंपियन मुंबई 11 अक्टूबर से चंडीगढ़ के खिलाफ 4 दिवसीय मुकाबला खेलेगी।

सूर्यकुमार ने रणजी मैच के लिए उपलब्ध रहने की जानकारी दी थी। उन्होंने चयनकर्ताओं को संदेश भी भेजा था। इसके बावजूद उन्हें स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया।

19 साल के आयुष म्हात्रे को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। यशस्वी जायसवाल भी स्क्वॉड में शामिल हैं। टी-20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें कप्तानी से हटा दिया और श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाया। यहां तक आयरलैंड, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान और जापान सीरीज की टीमों में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया। सिलेक्टर्स ने उनके खराब फॉर्म को वजह बताया। मुंबई के मुख्य चयनकर्ता राजेश पवार ने सूर्यकुमार को टीम में शामिल नहीं करने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार ने पिछले 18 महीनों से रेड-बॉल क्रिकेट नहीं खेला है। चयनकर्ता चाहते हैं कि वह पहले कुछ रेड-बॉल मैच खेलकर लय हासिल करें। पवार ने कहा, "सूर्यकुमार बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और मुंबई के लिए साबित प्रदर्शन कर चुके हैं।



सलमान आगा की जगह साहिबजादा फरहान को कमान, एशियन गेम्स फाइनल में भारत से हारी थी टीम

पाकिस्तान ने टी-20 कप्तान बदला

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ 9 से 13 अक्टूबर तक होने वाली 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए कप्तान बदल दिया है। सलमान अली आगा की जगह साहिबजादा फरहान को टीम की कमान सौंपी गई है। फरहान ने हाल ही में एशियन गेम्स में पाकिस्तान की कप्तानी की थी। उनकी टीम फाइनल में भारत से 19 रन से हारकर सिल्वर मेडल जीत सकी थी।

पाकिस्तान ने टी-20 टीम में बल्लेबाज हसन नवाज और तेज गेंदबाज नसीम शाह की वापसी भी कराई है।

वहीं, टेस्ट डेब्यू पर इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने वाले रजाउल्लाह को पहली बार टी-20 और वनडे टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को टी-20 और वनडे दोनों टीमों से बाहर रखा गया है। रिजवान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की जांच के दायरे में हैं। अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हार के बाद रिजवान समेत 7 खिलाड़ियों को वापस पाकिस्तान बुलाया गया था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज शॉन टेट को पाकिस्तान का नया बॉलिंग कोच बनाया गया है। वे इससे पहले बांग्लादेश की टीम के साथ काम कर रहे थे।

टेट के रहते बांग्लादेश ने इस साल पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती थी। पाकिस्तान ने उन्हें एशले नॉफ्के की जगह जिम्मेदारी दी है। नॉफ्के अब नीदरलैंड्स टीम के साथ काम करेंगे।

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 3 टी-20 मैचों की सीरीज रावलपिंडी में खेली जाएगी। सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू होगी और 13 अक्टूबर तक चलेगी। इसके बाद 18 अक्टूबर से पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच ट्राई सीरीज खेली जाएगी।



पाकिस्तान ने वनडे टीम में कप्तानी में बदलाव नहीं किया है। तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ही वनडे टीम के कप्तान बने रहेंगे। इस टीम में सलमान अली आगा और बाबर आजम भी शामिल हैं।

टी-20 टीम में विकेटकीपर की जिम्मेदारी ख्वाजा नफे को दी गई है। वहीं, वनडे टीम में घाजी घोरी को पहली पसंद के विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है।

एशियन गेम्स में फरहान की कप्तानी में फाइनल तक पहुंची थी टीम

साहिबजादा फरहान ने एशियन गेम्स में पाकिस्तान की कप्तानी की थी। टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया, जहां भारत ने उसे 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में हसन नवाज ने पाकिस्तान की ओर से 96 रन की पारी खेली थी। वे आखिरी गेंद पर आउट हुए और टीम लक्ष्य से 19 रन दूर रह गई। हसन नवंबर के बाद से पाकिस्तान की टी-20 टीम से बाहर चल रहे थे। एशियन गेम्स में प्रदर्शन के बाद उन्हें फिर मौका मिला है।

नसीम शाह की भी टी-20 टीम में वापसी

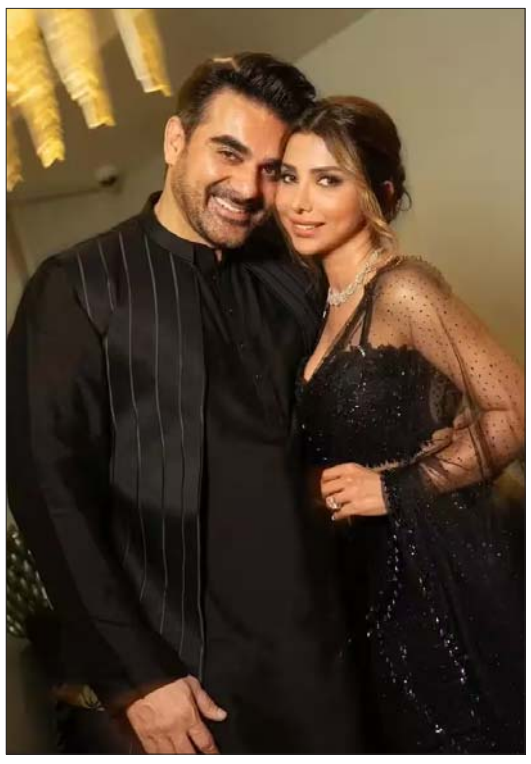
तेज गेंदबाज नसीम शाह को भी टी-20 टीम में वापस बुलाया गया है। उन्होंने आखिरी बार फरवरी में हुए टी-20 वर्ल्ड कप में इस फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेला था।

नसीम को श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ होने वाली ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान की वनडे टीम में भी शामिल किया गया है। यह ट्राई सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होगी।

इंग्लैंड के खिलाफ पिछले महीने बर्मिंघम में टेस्ट डेब्यू करने वाले रजाउल्लाह को भी टी-20 और वनडे टीम में जगह मिली है। उन्होंने अभी तक पाकिस्तान के लिए व्हाइट-बॉल क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है।

मनोरंजन

अस्पताल से डिस्चार्ज होने के महीनों बाद दिखे सलीम खान, सलमान समेत पूरा परिवार शामिल



अरबाज की बेटी सिपारा का पहला बर्थडे सेलिब्रेशन

नई दिल्ली। अरबाज खान और शूरा खान की बेटी सिपारा खान का सोमवार को पहला जन्मदिन मनाया गया।

मुंबई स्थित घर पर बर्थडे सेलिब्रेशन में खान परिवार के कई सदस्य शामिल हुए। सलीम खान, सलमान खान, सोहेल खान और अन्य लोग अरबाज के घर पहुंचे।

सामने आए वीडियो में सलीम खान कार से अरबाज के घर पहुंचते दिखे। उनके साथ उनकी पत्नी सलमा खान भी थीं।

बाद में सलीम खान सोहेल खान के साथ घर से बाहर निकले। सोहेल उन्हें कार तक चलने में मदद करते दिखे। हेलेन भी उनके साथ थीं। इस साल की शुरुआत में सलीम खान के ब्रेन हैमरेज के बाद करीब एक महीने अस्पताल में रहने की खबर सामने आई थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद वे मार्च 2026 में ईद के मौके पर पहली बार दिखाई दिए थे। अब कई महीनों बाद वे पब्लिकली दिखाई दिए हैं। अरबाज खान और शूरा खान ने अभी तक बेटी सिपारा की कोई भी ऐसी पूरी तस्वीर शेयर नहीं की है, जिसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा हो। हालांकि, दोनों कभी-कभी सोशल मीडिया पर बेटी की झलक शेयर करते हैं। नवंबर 2025 में दोनों ने बेटी के हाथों और पैरों की तस्वीरें शेयर की थीं।





सलमान और परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंचे

सलमान खान भी जन्मदिन की पार्टी में पहुंचे। उन्होंने काले रंग की फुल-स्लीव टी-शर्ट, नीली डेनिम जींस और काला चश्मा पहना था।

अर्पिता खान शर्मा अपनी बेटी आयत शर्मा के साथ पार्टी में पहुंचीं। अरबाज के बेटे अरहान और खान परिवार के कई अन्य सदस्य भी नजर आए।

अरबाज और शूरा ने 2023 में की थी शादी

अरबाज खान और शूरा खान ने 24 दिसंबर 2023 को शादी की थी। यह निजी समारोह मुंबई में अरबाज की बहन अर्पिता के घर हुआ था। शादी में परिवार के करीबी सदस्य और दोस्त शामिल हुए थे। 5 अक्टूबर 2025 को कपल की पहली संतान का जन्म हुआ था। बाद में दोनों ने सोशल मीडिया पर बेटी का नाम सिपारा खान बताया था।



सीजेपी-अभिजीत दीपके की आलोचना करने के दावों को बताया झूठ, बोले- मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों?

फर्जी मैसेज वायरल होने पर भड़के जावेद अख्तर

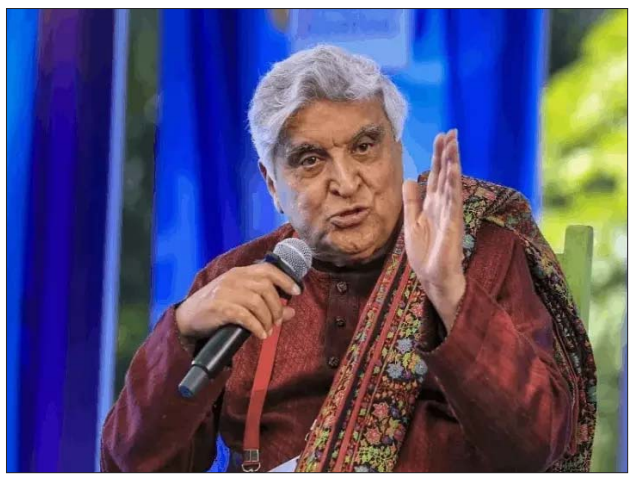
नई दिल्ली। जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मेसैज को पूरी तरह फेक बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस दावे को खारिज किया।

जावेद अख्तर ने सवाल उठाया कि अभिजीत दीपके और CJP की आलोचना के लिए उनके नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।

उन्होंने X पर लिखा, "मैं जावेद अख्तर, सभी को बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर फैला यह झूठा मेसैज कि मैंने CJP की आलोचना की है और अभिजीत दीपके को नीचा दिखाया है। यह पूरी तरह से फेक है। मुझे आश्चर्य है कि दीपके और CJP का विरोध करने वालों को मुझ जैसे व्यक्ति से विश्वसनीयता उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये हालत हो गई है? दुखद है।" कंचन गुप्ता ने रशीदी के बयान की खबर शेयर करते हुए जावेद अख्तर पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि अगर किसी हिंदू ने कहा होता कि मुसलमानों के 11-12 बच्चे होते हैं तो नसीरुद्दीन शाह भड़क जाते, जावेद अख्तर को बहुत बुरा लगता और LeLi गैंग सड़कों पर 'सर तन से जुदा...' के नारे लगाते हुए मार्च निकालता।



बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए फेक मैसेज में जावेद अख्तर ने अभिजीत दीपके और सीजेपी की आलोचना की थी। इसमें दीपके को अरविंद केजरीवाल की कठपुतली बताया गया था।



जावेद अख्तर और कंचन गुप्ता में सोशल मीडिया पर भिड़ंत

सोमवार को जावेद अख्तर और सूचना प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के एक बयान को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर भिड़ गए।

दरअसल, मौलाना साजिद रशीदी ने आबादी बढ़ाने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम परिवारों में पांच से ज्यादा बच्चे होना सामान्य है और छह बच्चों की संख्या उनके लिए लास्ट है। उन्होंने हिंदू परिवारों के कम बच्चे पैदा करने पर भी सवाल उठाए। रशीदी ने कहा था, हमारे यहां तो पांच से ऊपर होते हैं सबके। छह तो बिल्कुल लास्ट आंकड़ा है। कम से कम नहीं तो छह, आठ, दस और ग्यारह-बारह भी होते हैं। उन्होंने हिंदुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, रकम से कम दस पर तो आओ।

महाराष्ट्र साइबर पुलिस के समन पर हनी सिंह नहीं पहुंचे

गाड़ियों में शारीरिक संबंधों पर टिप्पणी मामले में मांगा और समय

नई दिल्ली। रैपर और सिंगर हनी सिंह सोमवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें दिल्ली में कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र साइबर के एक अधिकारी ने बताया कि हनी सिंह ने जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा है। साइबर पुलिस अब कोर्ट से अरेस्ट वारंट मांगेगी और उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने का प्रोसेस शुरू करेगी।

मामला दिल्ली के कॉन्सर्ट के एक वीडियो से जुड़ा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें हनी सिंह गाड़ियों में शारीरिक संबंध बनाने का अश्लील संदर्भ देते दिखे थे। हनी सिंह की टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद साइबर पुलिस में शिकायत की गई और केस दर्ज हुआ। मामले को लेकर महाराष्ट्र नोडल साइबर पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "हमने यो यो हनी सिंह को समन भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और उन्होंने कुछ समय मांगा है।"अधिकारी ने कहा कि एजेंसी अब गिरफ्तारी वारंट के लिए संबंधित अदालत का रुख करेगी। हनी सिंह देश छोड़कर न जा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए लुक-आउट सर्कुलर भी जारी किया जाएगा। मामले को लेकर विवाद होने के बाद हनी सिंह ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वीडियो क्लिप को इस तरह एडिट किया गया, जिससे लोगों को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा था कि उनका कभी किसी को चोट पहुंचाने, अपमानित करने या ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था।

अपने कमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझाते हुए हनी सिंह ने कहा था कि उन्होंने एक जाने-माने गाइनेकोलॉजिस्ट से बात की थी। डॉक्टर ने युवाओं में अनसेफ सेक्स की वजह से सेक्सुअल इन्फेक्शन बढ़ने पर चिंता जताई थी।



सेना-पुलिस के ठिकानों पर मछली पकड़ने वाला जाल लगा रहे, दावा- इसमें ड्रोन फंसकर फट जाएंगे

पाकिस्तान का ड्रोन हमलों से बचने के लिए सस्ता तरीका

बचाव

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से बचने के लिए पुलिस और सेना अब मछली पकड़ने वाले जाल का इस्तेमाल कर रही है। अल जजीरा के मुताबिक, खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकियों और सुरक्षा ठिकानों के ऊपर कई मीटर की ऊंचाई पर ये जाल लगाए जा रहे हैं।

सुरक्षाकर्मियों का ऐसा मानना है कि हमलावर ड्रोन इन जालों में फंस सकते हैं। इससे ड्रोन हमले में होने वाला नुकसान 40 से 50% तक कम किया जा सकता है। हालांकि, सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस तरीके को पूरी तरह भरोसेमंद मानने से इनकार किया है।



पुलिस के मुताबिक, जाल लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आतंकियों ने हमले का तरीका बदल दिया है। अब वे गोलीबारी और मोर्टार के साथ ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू जिले में 29 जुलाई को सबसे घातक हमलों में से एक हुआ था। बम से भरे ड्रोन से पुलिस चौकी पर हमला किया। इसमें 11 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद कई घंटे तक चली मुठभेड़ में 15 हमलावर भी मारे गए। पुलिस के मुताबिक, इस साल खैबर पख्तूनख्वा के हंगू जिले में कम से कम 16 हमले हो चुके हैं। इसी वजह से यह जिला प्रांत के सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल है। ऐसे हमलों से बचने के लिए हंगू पुलिस ने कम लागत वाला तरीका अपनाया। पुलिस चौकी की छत और चारदीवारी के बीच कई मीटर ऊपर मछली पकड़ने वाले जाल लगाए गए। इससे चौकी के ऊपर एक तरह की जालीदार छत बन गई।

पेशावर के आतंकवाद और सुरक्षा विशेषज्ञ फिदा अदील ने बताया कि मछली पकड़ने वाले जाल से ड्रोन रोकना कोई नया तरीका नहीं है।

एक चेकपोस्ट पर करीब 1 लाख रुपए खर्च

हंगू के जिला पुलिस अधिकारी तारिक हबीब के मुताबिक, एक सामान्य पुलिस चेकपोस्ट को इस तरह के जाल से ढकने में करीब 1.4 लाख रुपए खर्च होते हैं।

खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक, हंगू के अलावा कोहाट, करक, बन्नू, लक्की मरवत और डेरा इस्माइल खान जैसे कम से कम 5 और संवेदनशील जिलों में भी पुलिस चौकियों और चेकपोस्ट पर ये जाल लगाए गए हैं।

प्रांत के कुछ इलाकों में सेना के ठिकानों पर भी 'एंटी-ड्रोन जाल' लगाए गए हैं। पुलिस ने इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रांतीय सरकार से अतिरिक्त पैसे भी मांगे हैं।



हंगू में पुलिस चेकपॉइंट पर सुरक्षा के लिए मछली पकड़ने वाला जाल लगाया गया है।

एक चेकपोस्ट पर करीब 1 लाख रुपए खर्च

इस्लामाबाद स्थित सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के कार्यकारी निदेशक इम्तियाज गुल ने इसे नासमझी वाला सस्ता तरीका बताया। उनके मुताबिक, आतंकियों का निशाना हमेशा पुलिस स्टेशन या चेकपोस्ट ही नहीं होते। ड्रोन का इस्तेमाल बड़े और जरूरी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जाता है, ताकि हमले का असर ज्यादा दिखाई दे और लोगों में डर पैदा हो। उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन के हवा में उठते ही उसे रोकने की क्षमता रखती हैं।

वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन को दिया गया फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार

न्यूट्रिनो की खोज के लिए मिला सम्मान

वाशिंगटन, एजेंसी

बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को साल 2026 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आइसक्यूबन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में अहम योगदान और अंतरिक्ष से धरती तक पहुंचने वाले बेहद ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो कण की खोज के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें यह सम्मान दिया है। हाल्जेन ने अपने करियर का बड़ा हिस्सा अमेरिका में बिताया।

दिसंबर 2026 में स्वीडन के स्टॉकहॉम में फ्रांसिस हाल्जेन को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल, डिप्लोमा और 11.5 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि भी मिलेगी।

आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जिसका विचार इस साल फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले फ्रांसिस हैल्जेन ने दिया था – दूर अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो को ट्रैक करती है। आइसक्यूब द्वारा लगातार इकट्ठा की जाने वाली न्यूट्रिनो इंटरैक्शन से शोधकर्ताओं को उन हिंसक स्थितियों के बारे में नई जानकारी मिलेगी जिनमें हाई-एनर्जी न्यूट्रिनो बन सकते हैं, और इससे पहले से अज्ञात ब्रह्मांडीय घटनाओं का भी पता चल सकता है।



2026 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाने वाले फ्रांसिस हैल्जेन ने महसूस किया कि साउथ पोल की बर्फ का इस्तेमाल न्यूट्रिनो कहे जाने वाले कणों को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।

फास्ट न्यूज

'जेन डो' के समर्थन में उतरे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के छात्र

वाशिंगटन। अमेरिका की प्रतिष्ठित आइवी लीग यूनिवर्सिटी कॉर्नेल में एक छात्रा के साथ कथित गैंगरेप के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के विरोध में और पीड़िता के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सोमवार को यूनिवर्सिटी परिसर में एक विशाल रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कैंपस में बढ़ती यौन हिंसा के खिलाफ संस्थान से कड़े और ठोस कदम उठाने की मांग की।

ट्रंप ने फोर्ट हुड गोलीबारी के दोषी निदाल हसन की मौत की सजा को दी मंजूरी

वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 2009 में टेक्सास के फोर्ट हुड में गोलीबारी करने वाले मेजर निदाल मलिक हसन को फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा देने की मंजूरी दे दी। सेना ने 1961 के बाद से मौत की सजा पर अमल नहीं किया है। पेंटागन के प्रवक्ता शान पार्नेल ने कहा कि आर्मी सेक्रेटरी सजा देने का समय और जगह तय करेंगे। आखिरकार हसन के लिए फैसले का दिन आ गया है। आर्मी साइकियाट्रिस्ट हसन एक मेडिकल बिल्डिंग में गया, जहां सैनिक अपना चेकअप करवा रहे थे। उसने अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और गोलीबारी शुरू कर दी।

खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें कम से कम चार सीमा शुल्क यानी कस्टम अधिकारियों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना दक्षिण वजीरिस्तान की सीमा से लगे डेरा इस्माइल खान जिले में हुई। कस्टम विभाग के ये अधिकारी वहां ड्यूटी पर तैनात थे, तभी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं।

स्पेन में किराएदार को घर से निकालने पर सरकार गिरी

87 साल की महिला महंगा किराया नहीं चुका पाई

मैड्रिड, एजेंसी

स्पेन में 87 साल की एक महिला को घर से निकालना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। महंगे किराए और लोगों को घर से निकाले जाने के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए।

मामला इतना बढ़ा कि सरकार को किराएदारों को राहत देने के लिए संसद में इमरजेंसी बिल लाने पड़े। लेकिन सरकार इन्हें पास नहीं करा सकी। इसके बाद प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने तय समय से करीब 8 महीने पहले आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। स्पेन में 29 नवंबर 2026 को वोटिंग होगी।

मामले की शुरुआत 23 सितंबर को हुई। मैड्रिड में 87 साल की मारिया डेल कार्मेन अबास्कल को उस घर से निकाल दिया गया, जहां वह करीब 70 साल से रह रही थीं।



यह घर अबास्कल परिवार के पास कई दशकों से किराए पर था। 2018 में घर के मूल मालिक ने पूरी इमारत एक रियल एस्टेट कंपनी को बेच दी। इसके बाद कंपनी और अबास्कल में किराए को लेकर विवाद शुरू हो गया। कंपनी ने किराया 500 यूरो से बढ़ाकर 2650 यूरो कर दिया। अबास्कल की मासिक पेंशन ही करीब 1,350 यूरो थी। यानी मांगा गया किराया उनकी पूरी मासिक आय से भी काफी ज्यादा था। इसी वजह से वह नया किराया देने की स्थिति में नहीं थीं। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया था।

हूती विद्रोहियों के खिलाफ साथ आए तीनों देश, पिछले महीने पाकिस्तान ने मदद से इनकार किया था

सऊदी अरब में तैनात होंगी पाकिस्तान-तुर्किये की फौज

> सऊदी अरब यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ जंग शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को यमन में उतार सकता है। इसका मकसद बाब अल-मंदेब स्ट्रेट को हूतियों के कब्जे से छुड़ाना और समुद्री व्यापार का रास्ता सुरक्षित करना है।

रियाद, एजेंसी

लाल सागर में हूती विद्रोहियों की बढ़ती ताकत ने अब सऊदी अरब को सीधे सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है। सऊदी समर्थित यमनी सेना ने हूतियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान और तुर्किये भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपने सैन्य बल तैनात करने की तैयारी में हैं।

सोमवार को रियाद में मक्का रक्षा समझौते की इमरजेंसी मीटिंग हुई। इसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने सामूहिक रक्षा व्यवस्था को सक्रिय करने और सऊदी अरब में सैन्य बलों की तेजी से तैनाती पर सहमति जताई। इससे पहले भी सऊदी ने पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी थी। हालांकि, पाकिस्तान ने सितंबर में मदद देने से इनकार कर दिया था। यरुशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने तब कहा था कि उसकी सेना किसी दूसरे देश की जमीन पर युद्ध में शामिल नहीं होगी। रियाद में सोमवार को हुई बैठक के साथ मक्का रक्षा समझौता औपचारिक रूप से लागू हो गया। इसके तहत एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। बैठक में तीनों देशों के वरिष्ठ रक्षा और सैन्य अधिकारी शामिल हुए। तुर्किये से विदेश मंत्री हाकान फिदान और रक्षा मंत्री याशार ग्यूलर, जबकि सऊदी अरब से विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान और रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान मौजूद रहे। पाकिस्तान की ओर से उप प्रधानमंत्री इशाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हुए।



हूती विद्रोही पीछे हटे, बाब अल-मंदेब पर सऊदी समर्थित गुट मजबूत

सितंबर में हूतियों ने यमन के लाल सागर तट पर तेजी से बढ़ते हुए मोचा शहर और बाब अल-मंदेब के आसपास के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इससे इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर हूतियों की पकड़ मजबूत हो गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। 5 अक्टूबर को सऊदी समर्थित यमनी सेना ने हूतियों के खिलाफ बड़ा जवाबी अभियान शुरू किया। यमनी सेना ने बाब अल-मंदेब के पास धुबाब इलाके और कई अहम ठिकानों पर दोबारा कब्जे का दावा किया। इसके बाद सेना मोचा की तरफ बढ़ी और यमनी सरकार ने शहर को भी हूतियों से वापस लेने का दावा किया। रॉयटर्स के मुताबिक, सरकारी बलों ने हूतियों को पिछले महीने कब्जे में लिए गए ज्यादातर इलाकों से पीछे धकेल दिया है।

धमाके में 15 साल के छात्र का हाथ उड़ा, 5 हजार गिरफ्तार, 87% गिरफ्तार नाबालिग

फ्रांस में शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन हिंसक हुआ

पेरिस, एजेंसी

फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। सितंबर में शुरू हुआ यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी का विरोध कर रहे हैं।

पिछले एक हफ्ते में छात्रों ने सैकड़ों स्कूलों को बंद कराया। आंदोलन के दौरान कई जगह छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई।

लेंस शहर में एक स्कूल के पास हुए धमाके में 15 साल के एक छात्र का हाथ उड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले पिछले हफ्ते 14 साल के ईडन नाम के छात्र के सिर पर आंसू गैस का गोला लगने की खबर सामने आई थी। उसके जबड़े में दो जगह फ्रैक्चर हुआ था और उसे बड़ी सर्जरी करानी पड़ी। प्रदर्शन के दौरान कम से कम 190 छात्र घायल हुए हैं, जबकि 5,060 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 87% नाबालिग हैं। आंदोलन की शुरुआत 21 सितंबर को पेरिस के एक स्कूल से हुई थी। छात्रों की मांग थी कि स्कूल में स्टाफ और संसाधनों की कमी दूर की जाए।



प्रदर्शन के दौरान कई जगह स्कूलों की नाकेबंदी की गई और कूड़ेदानों में आग लगाई गई। शिक्षा मंत्री एडुआर्ड जॉफ्रे के मुताबिक आंदोलन शुरू होने के बाद से 24 स्कूलों को जला दिया गया या उनमें तोड़फोड़ की गई।

स्कूल में अतिरिक्त स्टाफ भेजे जाने के बाद वहां की हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन तब तक दूसरे इलाकों में भी विरोध शुरू हो चुका था।



फ्रांस में ज्यादा संसाधन और फंडिंग की मांग को लेकर प्रदर्शन करता फायरफाइटर। हेलमेट पर लिखा है- 'गुस्से में'।

मंगलवार को देशभर में सबसे बड़े प्रदर्शन का ऐलान

मंगलवार को छात्रों के समर्थन में देशभर में प्रदर्शन की तैयारी है। प्रमुख छात्र संगठन यूनियन सिंडिकेल लिसेन ने लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की है।

शिक्षकों के संगठनों ने भी अपने सदस्यों से प्रदर्शन में शामिल होने को कहा है। छात्रों का कहना है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके मुकाबले कक्षाएं, शिक्षक और दूसरी सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबास्तियन लेकोर्नू ने छात्रों और शिक्षा कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ कदमों की घोषणा की है। उन्होंने स्कूलों में बदलाव लाने का वादा किया है। हालांकि, हिंसा को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि सरकार नरमी नहीं बरतेगी।

83% दुकानदार यूपीआई चार्ज देने को तैयार नहीं

खर्च ग्राहकों पर डाला तो 86% लोग यूपीआई पेमेंट नहीं करेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी

83% दुकानदार 15 अक्टूबर से लगने वाला यूपीआई चार्ज भरने को तैयार नहीं हैं। वहीं, अगर दुकानदार यह खर्च ग्राहकों पर डालते हैं, तो 86% लोग UPI से पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसे में कुल लेन-देन में 10% और पेमेंट संख्या में 4% की कमी आ सकती है।

लोकलसर्कल्स ने इसे लेकर एक सर्वे किया है जिसमें ये जानकारी सामने आई है। नए नियमों के मुताबिक 2,000 रुपए से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% चार्ज (MDR) लगेगा।

लोकलसर्कल्स ने देश के 242 जिलों में 32,000 से ज्यादा कारोबारियों पर किए गए सर्वे में पाया कि कि केवल 17% मर्चेंट्स ही 0.4% MDR का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं।

दुकानदारों को होने वाले कुल यूपीआई पेमेंट में 2,000 से बड़े पेमेंट गिनती के लिहाज से 5% से भी कम हैं। लेकिन वैल्यू के लिहाज से यह आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। कुल पैसों का लगभग 67% हिस्सा इन्हीं बड़े पेमेंट्स से आता है।



यह हर महीने करीब 6 लाख करोड़ बैठता है। यह रकम पूरे देश में होने वाले कुल यूपीआई लेनदेन की वैल्यू का लगभग 20% है। यानी बड़े लेनदेन भले ही संख्या में कम हों, लेकिन बाजार में घूमने वाले पैसों का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं से बनता है।

बयान: मालूम होने पर भी प्लेन क्यों उड़ाने दिया, ओमान बोला- किसी देश ने हमामी की जानकारी नहीं मांगी

हमलावर पायलट मुसीबत था : अमेरिकी उपराष्ट्रपति

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को कहा कि फ्लाईदुबई का को-पायलट हमाम अल-हमामी पहले से मुसीबत था। ये अमेरिकी इंटेलिजेंस नहीं बोल रहा, उसका इतिहास खुद गवाह है। इसके बावजूद उसे पैसेंजर विमान उड़ाने की अनुमति कैसे मिली, यह सवाल उठता है। हमामी पर 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला करने और विमान को क्रैश कराने का आरोप है। वहीं, ओमान ने कहा कि किसी दूसरे देश ने हमामी की बैकग्राउंड जांच के लिए जानकारी नहीं मांगी थी। ओमान के मुताबिक अगर किसी देश ने मांगी होती तो वह हमामी के कट्टरपंथी होने से जुड़ी उपलब्ध जानकारी जरूर साझा करता। ओमान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं हैं। ऐसे में जांच का एक अहम सवाल यह है कि हमामी को तेल अवीव जाने वाली फ्लाईदुबई की फ्लाइट में को-पायलट की ड्यूटी कैसे मिली।



वेंस बोले- ईरान कनेक्शन का सबूत नहीं

फ्लाईदुबई की घटना में ईरान की भूमिका के सवाल पर वेंस ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला, जिससे ईरान का कनेक्शन साबित हो। उन्होंने कहा-ईरान की भूमिका को लेकर मैं अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की बात पर भरोसा करूंगा। किसी आधिकारिक ऐलान से पहले मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है।



तेल अवीव की फ्लाइट में ड्यूटी कैसे मिली, इसकी जांच जारी

ओमान ने हमामी पर पहले ही जांच की थी

जेडी वेंस के मुताबिक ओमान के अधिकारियों ने पहले हमामी के व्यवहार को लेकर चिंता जताई थी। उसे उड़ान ड्यूटी से भी हटाया गया था, लेकिन बाद में फ्लाईदुबई ने उसे यात्री उड़ानों की जिम्मेदारी दे दी।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने 29 साल के हमामी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की थी। उसकी कट्टरपंथी विचारधारा में रुचि को लेकर चिंता जताई गई थी। 2024 में उसे इसी वजह से ओमान की सरकारी एयरलाइन की पायलट ट्रेनिंग से हटा दिया गया था। बाद में उसे दूसरी जिम्मेदारी दे दी गई। करीब 8 महीने पहले वह फ्लाईदुबई से जुड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ने अपनी जांच की जानकारी दूसरी एजेंसियों या एयरलाइंस को नहीं दी। फरवरी में जब फ्लाईदुबई ने हमामी को नौकरी दी, तब उसने उसकी पिछली नौकरी और रिकॉर्ड की पुष्टि के लिए ओमान से संपर्क नहीं किया।

वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

एफवाई27 के लिए 6.6% से बढ़ाकर 7.1% किया

नई दिल्ली, एजेंसी

वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने FY27 के लिए GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 6.6% बताया था। मंगलवार, 6 सितंबर को जारी लेटेस्ट रिपोर्ट 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में वर्ल्ड बैंक ने यह बात कही है। ग्लोबल ट्रेड और दुनिया में तनाव के बावजूद भारत की इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रही थी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में निवेश और घरेलू खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन का सबसे बड़ा योगदान रहा है।



गांव और शहर दोनों में मांग: अच्छी खेती, सरकारी से किसानों को सिधी सहायता और सब्सिडी के चलते डिमांड बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर टैक्स में राहत और जीएसटी कटौती के बाद शहरी खपत में भी उछाल देखने को मिला है।

एक्सपोर्ट बड़ाः ग्लोबल लेवल पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट ने उम्मीद से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसे FY27 की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर माना जा रहा है।

सप्लाई साइड पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ने ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है।

तमसा संकेत
tamsa.news@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्यादेवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित कराकर तमसा संकेत भवन शहजादपुर, अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश) (पिन कोड-224122) से प्रकाशित

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. 64107/96